नोएडा की नई उड़ान: सपनों को आकार देता विकास | सौज झील: परिंदों के आशियाने को मिली दुनिया की पहचान | पहाड़ की प्रतिभा, पहाड़ का भविष्य

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 । अंक 11 । नवंबर 2026 । ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

एक्सप्रेसवे से रोजगार तक
जनकल्याण से गांवों के विकास तक
बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर



हुनर को नई उड़ान,
युवाओं को रोजगार के नए अवसर



हरियाणा से स्वीडन तक
विकास की नई साझेदारी
(निवेश, तकनीक और रोजगार के वैश्विक अवसरों की दस्तक)



IFFCO KISAN DRONE

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

नैनो डीएपी



अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967

www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

इस अंक में





16 एक्सप्रेसवे से रोजगार तक, जनकल्याण से गांवों के विकास तक: बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर


05 विकास के नए क्षितिज पर उत्तर प्रदेश


14 पहाड़ की प्रतिभा, पहाड़ का भविष्य


18 पूर्वांचल में रोजगार की नई बुनाई


20 जब बेटी की उड़ान और बचपन की मुस्कान बने विकास की पहचान


26 यीडा में उद्योगों की नई उड़ान: 3,155 करोड़ के निवेश से खुलेंगे रोजगार के हजारों द्वार


44 बिहार में उद्योगों की नई सुबह: रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

मूल्यः 20 रुपये, नवंबर 2026

वर्ष-7 अंकः 11, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह

संपादक
अहमद हसन

सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तर प्रदेश-	**सी.बी. सिंह**
उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय

मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।

पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)

RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

विकास की असली कसौटी: जब बदलती है आम आदमी की जिंदगी

सड़कें, उद्योग और योजनाएं तभी सार्थक हैं, जब उनके लाभ से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव

किसी देश या प्रदेश की प्रगति को मापने के लिए उद्योग, चौड़ी सड़कें, आधुनिक शहर, बढ़ता निवेश और नई तकनीक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। लेकिन विकास की असली तस्वीर इन उपलब्धियों से आगे दिखाई देती है। वह उस परिवार के चेहरे पर उभरती है, जिसकी आमदनी बढ़ी है; उस युवा के आत्मविश्वास में नजर आती है, जिसे अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिला है; और उस महिला के जीवन में दिखती है, जिसने आत्मनिर्भर बनकर परिवार के भविष्य को नई दिशा दी है।

भारत आज आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार, आधारभूत संरचना और तकनीकी नवाचार के नए दौर से गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, आधुनिक विनिर्माण इकाइयां और डिजिटल सेवाएं भविष्य के भारत की आधारशिला तैयार कर रही हैं। ये प्रयास केवल भौतिक सुविधाओं का विस्तार नहीं करते, बल्कि रोजगार, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के नए रास्ते भी खोलते हैं।

हालांकि, किसी परियोजना की सफलता का आकलन केवल लागत, आकार या निर्माण की गति से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि उससे स्थानीय लोगों को कितने अवसर मिले, छोटे कारोबारों को कितना प्रोत्साहन मिला और आसपास की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया। जब विकास का लाभ स्थानीय समाज तक पहुंचता है, तभी बड़ी परियोजनाएं जनकल्याण का माध्यम बनती हैं।

रोजगार और आत्मनिर्भरता विकास के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हैं। युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावहारिक कौशल और उद्यम शुरू करने के अवसर देना समय की आवश्यकता है। महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना केवल सामाजिक सशक्तीकरण नहीं, बल्कि परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों की मजबूती का आधार है। स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर संभावनाएं व्यापक बनाई जा सकती हैं।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस तस्वीर का अनिवार्य हिस्सा हैं। किसान की समृद्धि के बिना समावेशी विकास अधूरा है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, बेहतर विपणन और तकनीक किसानों की आय बढ़ाने तथा गांवों में रोजगार सृजित करने में सहायक हो सकते हैं। गांवों को केवल श्रम देने वाले क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्यम और नवाचार के केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाएं जब जरूरतमंद तक समय पर और सरलता से पहुंचती हैं, तो उनका प्रभाव आंकड़ों से कहीं अधिक होता है। पारदर्शी व्यवस्था, प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की भागीदारी इन्हें स्थायी परिणामों में बदल सकती है।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और भावी पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रगति वही टिकाऊ है, जो वर्तमान की जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखे।

निर्माणशाला टाइम्स का मानना है कि विकास की असली कसौटी उपलब्धियों की गिनती नहीं, जीवन में आया बदलाव है। राष्ट्र की प्रगति का सबसे सुंदर दृश्य विशाल इमारत नहीं, बल्कि वह मुस्कान है, जो किसी के जीवन में आए बदलाव से जन्म लेती है। ■

विकास की यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी सफलता का सबसे विश्वसनीय प्रमाण आम नागरिक का बढ़ता विश्वास, सम्मानपूर्ण जीवन और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। आखिरकार, राष्ट्र की प्रगति का सबसे सुंदर दृश्य कोई विशाल इमारत नहीं, बल्कि वह मुस्कान है, जो किसी व्यक्ति के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जन्म लेती है।

विकास के नए क्षितिज पर उत्तर प्रदेश

सिंगापुर की विशेषज्ञता, यूपी की उद्यम शक्ति

औद्योगिक निवेश से आधुनिक शहरों तक साझेदारी का विस्तार। विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, स्वच्छ तकनीक और रोजगार के नए अवसरों पर टिकी उम्मीदें



उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पारंपरिक आर्थिक ताकत के साथ आधुनिक तकनीक, वैश्विक पूंजी और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का मेल नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। विशाल उपभोक्ता बाजार, कृषि संपदा, तेजी से विकसित होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क और बढ़ते औद्योगिक केंद्र प्रदेश को निवेश के मानचित्र पर नई पहचान दे रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में सिंगापुर के उद्योग जगत की उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिलचस्पी को एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है।

28 अक्टूबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक ने इस उभरती साझेदारी को नया आयाम दिया। बातचीत का दायरा केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें औद्योगिक विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और शहरी नियोजन जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्र भी शामिल रहे।

फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल का उत्तर प्रदेश आना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष आर्थिक संबंधों को ठोस परियोजनाओं में बदलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

निवेश की नई भाषा: प्रस्ताव से उत्पादन तक

औद्योगिक विकास की सफलता केवल निवेश की घोषणाओं या समझौता ज्ञापनों की संख्या से तय नहीं होती। असली उपलब्धि तब होती है, जब किसी परियोजना की नींव कारखाने में बदलती है, मशीनें उत्पादन शुरू करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा कारोबार के नए अवसर पैदा होते हैं।

लखनऊ की बैठक में यही सोच प्रमुखता से उभरी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि समझौते से लेकर निर्माण और उत्पादन शुरू होने तक राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। निवेशकों के लिए भूमि, प्रशासनिक समन्वय और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहयोग का यह आश्वासन उत्तर प्रदेश की निवेश रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बैठक के दौरान मेसर्स ग्रेटर नासिक इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण परियोजना के लिए पात्रता प्रमाणपत्र सौंपा गया। सेक्टर-8डी में 50 एकड़ भूमि पर लगभग 775 करोड़ रुपये की लागत से 'यूनिवर्सल पैकेजिंग हब' विकसित करने की योजना है। परियोजना में सिंगापुर से प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी शामिल है और इससे 1,880 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।

यह पहल इसलिए उल्लेखनीय है कि पैकेजिंग



मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर सिंगापुर डेलीगेशन के साथ बैठक करते हुये।





जैसे उद्योग का प्रभाव एक कारखाने की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, भंडारण, रखरखाव और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से आसपास के कारोबारी परिवेश को भी गति मिल सकती है।

जेवर: जहां आकार ले सकती है औद्योगिक भविष्य की नई तस्वीर

उत्तर प्रदेश के बदलते औद्योगिक भूगोल में जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मालवाहक गलियारों से जुड़ाव इस क्षेत्र को विनिर्माण तथा लॉजिस्टिक्स के लिए विशेष संभावनाओं वाला केंद्र बनाता है।

सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के सामने जेवर के निकट 'सिंगापुर सिटी' और हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। परिकल्पना यह है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग, वेयरहाउसिंग, आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित व्यावसायिक सेवाओं के लिए एक सुव्यवस्थित औद्योगिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए।

यदि यह योजना प्रभावी क्रियान्वयन तक पहुंचती है, तो क्षेत्र में निवेश के साथ-साथ तकनीकी सेवाओं, परिवहन, आतिथ्य और स्थानीय कारोबार के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे बड़े विकास मॉडल की वास्तविक सफलता भूमि उपयोग, पर्यावरणीय संतुलन, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर भी निर्भर करेगी।

मोबाइल विनिर्माण से आगे, तकनीक की अगली छलांग

उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, देश के कुल मोबाइल उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण में लगभग 60 प्रतिशत है। इस औद्योगिक आधार को अब अधिक तकनीक-प्रधान क्षेत्रों से जोड़ने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी मांग डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ बढ़ रही है। सिंगापुर की तकनीकी विशेषज्ञता, निवेश अनुभव और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी नेटवर्क का लाभ उत्तर प्रदेश को इन क्षेत्रों में मिल सकता है।

लेकिन इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए केवल निवेश पर्याप्त नहीं होगा। कुशल इंजीनियरों और तकनीशियनों की उपलब्धता, निर्बाध बिजली, जल प्रबंधन, डिजिटल कनेक्टिविटी और अनुसंधान आधारित औद्योगिक वातावरण भी जरूरी होंगे। यदि इन पहलुओं पर समानांतर काम होता है, तो प्रदेश पारंपरिक विनिर्माण से उच्च मूल्यवर्धित उद्योगों की ओर बढ़ सकता है।

खेतों की उपज को मिलेगा मूल्यवर्धन का नया रास्ता

उत्तर प्रदेश की आर्थिक पहचान में कृषि की केंद्रीय भूमिका है। ऐसे में औद्योगिक विकास को खेती से जोड़ना प्रदेश के लिए दीर्घकालिक



महत्व रखता है। एग्रीकॉर्प इंटरनेशनल के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत सोया प्रोटीन आइसोलेट और चना प्रोटीन कंसंट्रेट के उत्पादन के लिए आधुनिक ग्रीनफील्ड विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना सामने आई है।

यह परियोजना कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। जब कृषि उपज को परिष्कृत खाद्य उत्पादों में बदला जाता है, तो भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग और परिवहन जैसी गतिविधियों की मांग भी बढ़ती है।

इसका व्यापक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय उत्पादकों, किसान समूहों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना आवश्यक होगा। इस तरह कृषि और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकता है।

कचरे से संसाधन तक: स्वच्छ तकनीक की बढ़ती भूमिका

आधुनिक शहरों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन भी शामिल है। तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में कचरे का निस्तारण केवल सफाई व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़ा सवाल है।

ब्लू प्लैनेट एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस के साथ हुए समझौते में नोएडा के सेक्टर-145 में लगभग 7.5 लाख टन पुराने कचरे के उपचार और सहारनपुर में प्रतिदिन 350 टन ताजा कचरे के प्रसंस्करण संयंत्र की योजना शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए 250 से 350 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 100 से 120 रोजगार अवसरों का उल्लेख किया गया है।

ऐसी परियोजनाओं का महत्व केवल निवेश या रोजगार तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से पुराने कचरे का उपचार, नए कचरे का प्रसंस्करण और उपयोगी संसाधनों की संभावित पुनर्प्राप्ति शहरों को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकती है। इसका प्रभाव परियोजनाओं की तकनीकी गुणवत्ता, पर्यावरणीय मानकों और निरंतर संचालन पर निर्भर करेगा।

पर्यटन और शहरों को मिलेगी वैश्विक दृष्टि

उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी केवल कारखानों और औद्योगिक गलियारों तक सीमित नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों में विश्वस्तरीय होटल, कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक पर्यटन सुविधाओं और वेलनेस परियोजनाओं के विकास में सिंगापुर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की संभावना पर जोर दिया। लखनऊ और नई टाउनशिप्स के सुनियोजित विकास में भी आधुनिक शहरी नियोजन उपयोगी हो सकता है।

सिंगापुर का अनुभव घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, परिवहन और सुव्यवस्थित विकास के संदर्भ में प्रासंगिक है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप इस अनुभव का उपयोग किया जाए, तो पर्यटन सुविधाओं के साथ शहरों की कार्यक्षमता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के अवसर मिल सकते हैं।

वैश्विक साझेदारी की असली पहचान

सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और निवेश संबंधी व्यवस्थाओं की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल उद्योग जगत के सदस्यों की रुचि यह दर्शाती है कि प्रदेश की संभावनाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय कारोबारी समुदाय में संवाद आगे बढ़ रहा है।

फिर भी, किसी भी निवेश साझेदारी की असली पहचान उसके परिणामों से बनती है। प्रस्तावित परियोजनाओं का समय पर पूरा होना, रोजगार की गुणवत्ता, स्थानीय उद्योगों की भागीदारी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी ऐसे मानक होंगे, जिन पर इस सहयोग की सफलता को परखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच उभरता आर्थिक संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तकनीक, विनिर्माण, कृषि, स्वच्छता और शहरी विकास जैसे विविध क्षेत्र एक साथ दिखाई देते हैं। यह साझेदारी प्रदेश को वैश्विक निवेश से जोड़ने के साथ स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं के बेहतर उपयोग का अवसर भी देती है।

अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि घोषणाओं और समझौतों से आगे बढ़कर ये योजनाएं कितनी तेजी से धरातल पर उतरती हैं। यदि निवेश उत्पादन, कौशल विकास और व्यापक रोजगार में बदलता है, तो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति मिल सकती है। ■

बदलते मौसम पर **तकनीक की पैनी नजर: सुरक्षित उत्तर प्रदेश** की नई तैयारी

पांच डॉप्लर वेदर रडार से मौसम निगरानी को मिलेगी मजबूती, आपदा से मुकाबले की तैयारी को मिल सकता है नया आयाम

मौसम की करवट कभी खेतों में खुशहाली लेकर आती है, तो कभी तेज बारिश, आंधी और तूफान के रूप में बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में मौसम के मिजाज को समय रहते समझ लेना केवल सुविधा नहीं, बल्कि जनजीवन, आजीविका और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ी जरूरत है। आधुनिक तकनीक के इस दौर में उत्तर प्रदेश में पांच डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना की पहल मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने की तैयारी को नई संभावनाएं प्रदान करता है। डॉप्लर वेदर रडार की खासियत यह है कि यह वर्षा की तीव्रता, बादलों की गति और आंधी-तूफान से जुड़ी गतिविधियों का आकलन करने में मदद करता है। इससे मौसम वैज्ञानिकों को मौसमी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और पूर्वानुमान को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सकती है।

किसानों के लिए समय पर सूचना, बेहतर तैयारी

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम में अचानक बदलाव किसानों की मेहनत और फसल की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अधिक प्रभावी मौसम निगरानी से किसानों को बारिश, तेज हवाओं और संभावित खराब मौसम के प्रति समय रहते सतर्क करने में मदद मिल सकती है। इसका लाभ खेती-किसानी के कार्यों की योजना बनाने और जोखिम कम करने में मिल सकता है।

आपदा प्रबंधन में बढ़ेगी तैयारी की अहमियत

भारी बारिश, आंधी और तूफान जैसी परिस्थितियों में समय पर सूचना प्रशासन को राहत एवं बचाव की तैयारी के लिए अतिरिक्त अवसर दे सकती है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की आशंका, संवेदनशील इलाकों में सतर्कता और आवश्यक संसाधनों की तैनाती जैसे कार्यों में मौसम संबंधी जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।

हालांकि, किसी भी तकनीकी व्यवस्था की सफलता केवल उपकरणों की स्थापना से तय नहीं होती। इसके लिए रडार से प्राप्त आंकड़ों का



प्रभावी विश्लेषण, मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय तथा चेतावनियों का आम नागरिकों तक समय पर पहुंचना भी जरूरी है।

तकनीक से सुरक्षा तक का सफर

पांच डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना की पहल उत्तर प्रदेश में मौसम निगरानी को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण संभावना प्रस्तुत करती है। इसका व्यापक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग समय रहते निर्णय लेने और आम लोगों को सतर्क करने में किया जाए।

बदलते मौसम के दौर में सटीक जानकारी ही बेहतर तैयारी की पहली शर्त है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक मौसम निगरानी तंत्र का विस्तार इसी सोच को मजबूती देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जो भविष्य में जनसुरक्षा, कृषि संरक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए उपयोगी आधार बन सकता है। ■

सुरक्षा से स्वावलंबन तक
बदलती नारी शक्ति की नई तस्वीर

मिशन शक्ति फेज-6.0 के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों, आत्मविश्वास और अवसरों पर जोर



किसी समाज की प्रगति का वास्तविक पैमाना यह नहीं कि वहां महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, बल्कि यह भी है कि वे कितनी सुरक्षित हैं, अपने निर्णय कितने स्वतंत्र रूप से ले पाती हैं और आर्थिक रूप से कितनी आत्मनिर्भर हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का छठा चरण इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित यह अभियान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, जागरूकता तथा स्वावलंबन को केंद्र में रखता है।

महिला सशक्तीकरण की राह में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी का अभाव है। कई बार जानकारी की कमी के कारण महिलाएं उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद शिकायत नहीं कर पातीं या उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पातीं। ऐसे में जागरूकता अभियान उन्हें अपने अधिकारों को समझने, जरूरत पड़ने पर सहायता लेने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का भरोसा दे सकते हैं।

मिशन शक्ति की उपयोगिता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। बालिकाओं में आत्मविश्वास, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता और समाज में समानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना भी इसकी व्यापक भावना का हिस्सा है। परिवार, शिक्षण संस्थान, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान—हर जगह सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

आर्थिक स्वावलंबन इस बदलाव का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। जब महिलाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, तो उनकी भूमिका परिवार की सीमाओं से आगे बढ़कर समाज और अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है। इसलिए महिला सुरक्षा के साथ आजीविका और आत्मनिर्भरता के अवसरों को जोड़ना इस अभियान के प्रभाव को अधिक व्यापक बना सकता है।

हालांकि, किसी भी अभियान की वास्तविक सफलता केवल गतिविधियों की संख्या से नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में आए बदलाव से मापी जानी चाहिए। शिकायतों पर संवेदनशील कार्रवाई, जरूरतमंदों तक सहायता की पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं।

मिशन शक्ति फेज-6.0 की असली उपलब्धि तब होगी, जब प्रदेश की हर बेटी निर्भय होकर अपने सपनों की ओर बढ़ सके और हर महिला सम्मान के साथ अपने भविष्य का निर्णय लेने में सक्षम हो। यही सुरक्षित, संवेदनशील और सशक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में सार्थक कदम है। ■

परंपरागत चिकित्सा से आधुनिक संभावनाओं तक: आयुष क्षेत्र में नई उड़ान की तैयारी

आयुष पॉलिसी-2026 से अनुसंधान, निवेश और युवाओं के रोजगार को मिल सकती है नई गति

भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सदियों से स्वस्थ जीवन की अवधारणा का हिस्सा रही हैं। आज बदलती जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी विधाओं के प्रति लोगों की रुचि नए अवसर पैदा कर रही है। उत्तर प्रदेश अब इसी संभावनाशील क्षेत्र को आधुनिक जरूरतों से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नवंबर में प्रस्तावित आयुष पॉलिसी-2026 इस बदलाव को नई गति देने की उम्मीद जगाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य आयुष क्षेत्र को केवल पारंपरिक उपचार तक सीमित रखने के बजाय उसे अनुसंधान, नवाचार, निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक ढांचे से जोड़ना है। नई नीति के माध्यम से आयुष आधारित संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू अनुसंधान और नवाचार है। पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन, गुणवत्ता परीक्षण और आधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सकता है। इससे आयुष उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और बाजार में उनकी संभावनाओं को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, इस दिशा में वैज्ञानिक प्रमाणों और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन बेहद जरूरी होगा।

आयुष क्षेत्र का विस्तार रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोल सकता है। औषधीय पौधों की खेती, हर्बल उत्पादों का निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वेलनेस सेवाओं और आयुष पर्यटन जैसे क्षेत्रों में युवाओं तथा छोटे उद्यमियों के लिए अवसर विकसित हो सकते हैं। इससे स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।



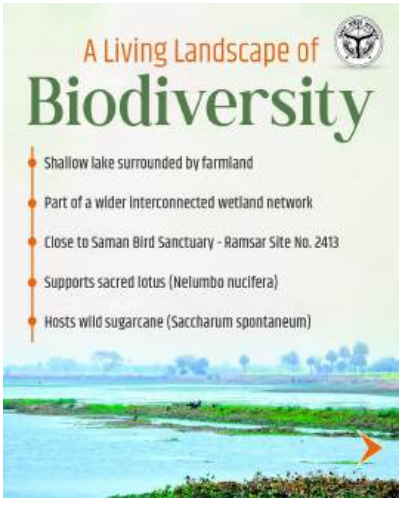
आयुष की परंपरा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने की यह पहल उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता के नए द्वार खोलने की संभावना रखती है।

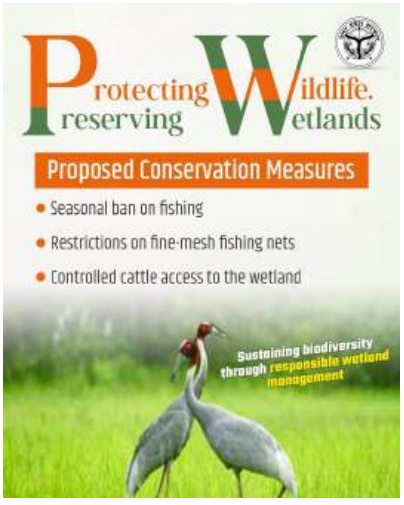
उत्तर प्रदेश के लिए आयुष पॉलिसी-2026 की सफलता इस बात से तय होगी कि इसका लाभ बड़े निवेशकों के साथ छोटे उद्यमियों, किसानों और आम नागरिकों तक किस तरह पहुंचता है। यदि बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गुणवत्ता आधारित सेवाओं को समान महत्व मिलता है, तो आयुष क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनस्वास्थ्य में सार्थक योगदान दे सकता है। ■

सौज झील: परिंदों के आशियाने को मिली दुनिया की पहचान

मैनपुरी की इस खूबसूरत आर्द्रभूमि में बसती है प्रकृति की अनमोल दुनिया









कभी झीलों की पहचान उनके शांत पानी और किनारों पर पसरी हरियाली से होती थी, तो कभी सुबह की पहली किरण के साथ गूंजती पक्षियों की आवाजों से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित सौज झील भी प्रकृति की ऐसी ही अनमोल धरोहर है, जहां हजारों परिंदों की मौजूदगी जीवन और पर्यावरण के खूबसूरत रिश्ते को बयां करती है। अब रामसर स्थल के रूप में मिली वैश्विक पहचान ने इस झील को एक नई प्रतिष्ठा दी है।

सौज झील की खासियत सिर्फ इसका प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि यहां पनपने वाली समृद्ध जैव विविधता भी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह आर्द्रभूमि 30 हजार से अधिक जलपक्षियों का आश्रय है। इनमें आकर्षक सारस क्रेन और दुर्लभता की चिंता से जुड़े ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जैसे पक्षी भी शामिल हैं। इन परिंदों की मौजूदगी बताती है कि झीलें केवल पानी का ठिकाना नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों की जिंदगी का आधार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच सौज झील की यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक विरासत की ओर ध्यान खींचती है। हालांकि, इस पहचान का असली अर्थ तब सामने आएगा, जब झील का पानी स्वच्छ रहे, आसपास का प्राकृतिक परिवेश सुरक्षित हो और यहां आने वाले पक्षियों को अनुकूल वातावरण मिलता रहे।

आज जब विकास की रफ्तार के बीच प्रकृति को बचाने की चुनौती लगातार बढ़ रही है, तब सौज झील उम्मीद जगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी स्थान की असली खूबसूरती केवल उसकी भौगोलिक पहचान में नहीं, बल्कि वहां सुरक्षित सांस लेती जैव विविधता में भी छिपी होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच सौज झील की यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक विरासत की ओर ध्यान खींचती है।

सौज झील को मिली वैश्विक पहचान मैनपुरी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास है। आखिर, परिंदों के लिए बचाया गया एक आशियाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर, संतुलित और जीवंत दुनिया बचाने की कोशिश है। ■

देहरादून में तकनीक और नवाचार को नई उड़ान, स्टार्टअप्स के लिए खुला संभावनाओं का नया द्वार

30 हजार वर्ग फुट में विकसित आधुनिक केंद्र से युवाओं को मिलेगा उद्यम शुरू करने का अवसर, 17 स्टार्टअप्स को 4.25 करोड़ की शुरुआती वित्तीय सहायता



पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा देहरादून अब तकनीक, नवाचार और नए उद्यमों की संभावनाओं को भी आकार दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाला यह शहर धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप गतिविधियों के उभरते केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की नई इन्क्यूबेशन सुविधा का शुभारंभ राज्य के युवाओं और तकनीकी उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में स्थापित इस चार मंजिला केंद्र का उद्घाटन 23 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। लगभग 30 हजार वर्ग फुट क्षेत्र में फैली यह सुविधा उन युवाओं को आधुनिक कार्यस्थल और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने तकनीकी विचारों को सफल व्यवसाय में बदलना चाहते हैं।

विचारों को कारोबार में बदलने का अवसर

किसी नए उद्यम की शुरुआत केवल एक अच्छे विचार से नहीं होती। उसके लिए उपयुक्त कार्यस्थल, तकनीकी संसाधन, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और उद्योग जगत से संपर्क भी जरूरी होता है। शुरुआती चरण में इन सुविधाओं का खर्च कई युवा उद्यमियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। एसटीपीआई की नई सुविधा इसी अंतर को कम करने की क्षमता रखती है।

यहां अर्ध-सुसज्जित कार्यालय, तेज इंटरनेट, बैठक कक्ष, सम्मेलन कक्ष, सभागार और नेटवर्क संचालन केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक कार्यस्थल के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण मिलने से नए उद्यमियों को अपने उत्पाद विकसित करने, व्यावसायिक साझेदारियां बनाने और कारोबार के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उत्तराखंड में 1,700 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यह संख्या राज्य में उद्यमिता के प्रति बढ़ती



रुचि और नई संभावनाओं का संकेत देती है।

आर्थिक सहायता से मजबूत होती उद्यमिता

स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती पूंजी की उपलब्धता अक्सर निर्णायक साबित होती है। एसटीपीआई की अगली पीढ़ी की इन्क्यूबेशन योजना के अंतर्गत आयोजित चुनौती कार्यक्रमों में 52 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। इनमें से 17 को कुल 4.25 करोड़ रुपये की शुरुआती वित्तीय सहायता दी गई है, जबकि 26 से अधिक स्टार्टअप्स को 90-90 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली है।

ऐसी मदद युवाओं को अपने विचारों पर प्रयोग करने, उत्पादों का विकास करने और बाजार की जरूरतों के अनुरूप समाधान तैयार करने का अवसर देती है। मार्गदर्शन और उद्योग जगत से जुड़ाव मिलने पर इन प्रयासों के आगे बढ़ने की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं।

पहाड़ों में रोजगार के नए रास्ते

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए तकनीक आधारित उद्यमिता का विस्तार विशेष महत्व रखता है। इससे रोजगार के अवसर केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को अपने ही राज्य में काम करने, नए व्यवसाय शुरू करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिल सकता है।

नई सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की जरूरत पर जोर दिया। राज्य के आईटी एवं सुशासन मंत्री प्रदीप बत्रा ने भी तकनीक और उद्यमिता को राज्य की प्रगति से जोड़ने की आवश्यकता रेखांकित की। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह के विकास जैसे प्रयास इस दिशा में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं।

एसटीपीआई देहरादून वर्ष 2001 से राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सहयोग दे रहा है। नई सुविधा से पहले से उपलब्ध लगभग 19,533 वर्ग फुट क्षेत्र वाले इन्क्यूबेशन केंद्र के साथ तकनीकी उद्यमों के लिए बुनियादी ढांचे का और विस्तार होगा।



प्रतिभा को स्थानीय अवसरों से जोड़ने की जरूरत

देहरादून की असली ताकत यहां का शैक्षणिक वातावरण, युवा प्रतिभा और बदलती आर्थिक आकांक्षाएं हैं। यदि इन क्षमताओं को तकनीकी प्रशिक्षण, निवेश, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच का सहारा मिलता है, तो राज्य में नए उद्यमों के विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

नई इन्क्यूबेशन सुविधा इसी संभावना को मजबूत करने वाला मंच है। इसकी सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि यहां से कितने नए उद्यम विकसित होते हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिलता है और कितने नवाचारी उत्पाद बाजार तक पहुंचते हैं।

उत्तराखंड के लिए यह पहल केवल एक नए भवन की शुरुआत नहीं, बल्कि स्थानीय प्रतिभा को अवसर देने और पहाड़ों में रोजगार के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक सार्थक कदम है। ■



पहाड़ की प्रतिभा पहाड़ का भविष्य

स्वरोजगार, स्टार्टअप और नवाचार से विकसित उत्तराखण्ड की नई कहानी

निर्माणशाला टाइम्स

उत्तराखण्ड की पहचान उसकी ऊंची पर्वत चोटियों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। लेकिन आज इस देवभूमि की एक नई पहचान भी उभर रही है—अपने संसाधनों से रोजगार पैदा करने वाले युवा, गांव लौटकर उद्यम खड़े करने वाले लोग और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ने वाले नवाचारकर्ता। ये प्रयास बताते हैं कि पहाड़ की चुनौतियों के बीच भी अवसरों की कमी नहीं, जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित 'विकसित उत्तराखण्ड–यात्रा जारी है' संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे उद्यमियों, किसानों, महिलाओं और नवाचारकर्ताओं की ऐसी ही प्रेरक कहानियां सामने आईं। इन अनुभवों में रोजगार की तलाश से आगे बढ़कर रोजगार देने की सोच दिखाई दी। नियोजन विभाग और देवभूमि डायलॉग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संवाद में प्रदेश की विकास यात्रा में स्थानीय प्रतिभा की भूमिका पर विशेष जोर रहा।

700 से 1700 से अधिक स्टार्टअप: बदलती उद्यमिता की तस्वीर

पिछले पांच वर्षों में उत्तराखण्ड में स्टार्टअप की संख्या लगभग 700 से बढ़कर 1700 से अधिक होना राज्य में उद्यमिता के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और नए प्रयोगों की क्षमता इन संभावनाओं को वास्तविक अवसरों में बदल सकती है।

ऊधमसिंह नगर के विकास कुमार शाह और उनकी पत्नी ने स्टार्टअप के माध्यम से अपने कारोबार को 10 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर तक पहुंचाया है। यह उदाहरण दिखाता है कि उद्यमिता केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों से भी बड़े व्यावसायिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

एक गाय से शुरू हुआ सफर, डेयरी कारोबार तक पहुंची मेहनत

उत्तरकाशी के जयप्रकाश की कहानी ग्रामीण उद्यमिता का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने एक गाय से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने काम का विस्तार किया। आज उनके पास पांच बद्री गाय और आठ देशी गाय हैं। यह सफर बताता है कि सीमित संसाधनों से शुरू हुआ प्रयास भी निरंतर मेहनत और उचित सहयोग से आगे बढ़ सकता है। पौड़ी के नवीन पटवाल गुच्छी मशरूम के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं, सोमेश्वर के ललित खाती एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे प्रयास कृषि को केवल पारंपरिक आजीविका नहीं, बल्कि उद्यम और आय के विविध स्रोतों से जोड़ते हैं।

गांव लौटने में भी है तरक्की की राह

पलायन उत्तराखण्ड की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों में शामिल रहा है। ऐसे में चमोली के राजेश की पहल विशेष महत्व रखती







है। उन्होंने गांव लौटकर रोजमेरी और अन्य हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में काम शुरू किया और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किए।

चमोली के घेस क्षेत्र में डॉ. हरपाल नेगी औषधीय वनस्पति कुटकी की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस कार्य से 300 से अधिक लोग जुड़े हैं और सामूहिक रूप से लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। यह उदाहरण स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और सामूहिक प्रयासों की आर्थिक क्षमता को सामने लाता है।

महिलाओं की मेहनत से खुल रहे नए रास्ते

उत्तराखण्ड में महिला उद्यमिता की तस्वीर भी लगातार विविध हो रही है। नैनीताल की कमला देवी वाहनों के टायरों की मरम्मत का काम कर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। पिरूल से उपयोगी उत्पाद तैयार करने वाली गीता पंत और सुमन पांथरी ने स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल की संभावनाओं को सामने रखा है। वहीं, कल्पना बिष्ट मोटे अनाज से बने उत्पादों की बेकरी संचालित कर रही हैं।

इन उदाहरणों का महत्व केवल आर्थिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं की कार्यक्षमता, आत्मनिर्भरता और परंपरागत भूमिकाओं से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने की क्षमता को भी रेखांकित करते हैं।

नवाचार से लेकर वैश्विक रोजगार तक

चम्पावत के राहुल नरियाल ने सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाली कार तैयार करने का अपना अनुभव साझा किया। यह प्रयास स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रयोगों और नवाचार की संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

दूसरी ओर, टिहरी की सपना राणा ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार हासिल किया। उनकी कहानी कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के बीच संबंध को दर्शाती है। वहीं, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनीता शर्मा थपलियाल के प्रयास सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण पक्ष को सामने लाते हैं।

विकास की असली कसौटी: अवसर गांव तक पहुंचें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नवाचार राज्य की विकास यात्रा को गति दे रहे हैं। पर्यटन और ऊर्जा के साथ कृषि, स्थानीय उत्पादों तथा स्वरोजगार में भी आगे बढ़ने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

हालांकि, इन प्रेरक प्रयासों को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए बाजार तक आसान पहुंच, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बेहतर परिवहन और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग पर निरंतर ध्यान देना होगा। इससे छोटे उद्यमों को टिकाऊ बनाने और ग्रामीण युवाओं के लिए प्रदेश में ही बेहतर अवसर विकसित करने में मदद मिल सकती है।

उत्तराखण्ड की विकास यात्रा का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि बदलाव की कहानियां अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। वे गांवों, खेतों, छोटे उद्यमों और स्थानीय नवाचारों से भी आकार ले रही हैं। जब पहाड़ का युवा अपने हुनर पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा, स्थानीय संसाधनों से आजीविका के नए रास्ते बनेंगे और महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे, तभी विकसित उत्तराखण्ड का सपना जमीन पर और अधिक मजबूत दिखाई देगा। ■





एक्सप्रेसवे से रोजगार तक, **जनकल्याण से गांवों के विकास तक:** बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर

औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक हब, ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी और गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर; समयबद्ध क्रियान्वयन से विकास को जनजीवन से जोड़ने की पहल।

किसी प्रदेश की विकास यात्रा तब सार्थक बनती है, जब चौड़ी सड़कों पर दौड़ते वाहनों के साथ उद्योगों को गति मिले, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलें और गांवों में रहने वाले परिवारों तक शिक्षा, आवास तथा बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने और गरीब परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने तक की पहल विकास के इसी व्यापक स्वरूप को सामने रखती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की आठवीं बैठक में प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि बड़ी परियोजनाएं केवल फाइलों और प्रक्रियाओं तक सीमित न रहें, बल्कि निर्धारित समय में धरातल पर उतरकर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान दें।



एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब से औद्योगिक संभावनाओं का विस्तार

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए चार निविदाएं प्राप्त हुई हैं, जबकि फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 80 से 91 प्रतिशत तक भूमि उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।

बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों को माल की ढुलाई, किसानों को बाजार तक पहुंच और कारोबारियों को परिवहन संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसका लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचने पर छोटे उद्यमों, परिवहन सेवाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की 323 हेक्टेयर भूमि में से 301 हेक्टेयर पर

कब्जा प्राप्त होना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। ऐसी परियोजनाएं भंडारण, माल वितरण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक बन सकती हैं।

गरीब परिवारों तक पहुंचे योजनाओं का वास्तविक लाभ

विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षा है। जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित





12.50 लाख परिवारों में से करीब नौ लाख परिवार आवास के पात्र पाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,725 आवास स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

इन परिवारों को श्रमिक पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को केवल चिन्हित करने के बजाय उन्हें संबंधित योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने पर जोर दिया।

यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरतमंद परिवार के लिए पक्का घर, स्वास्थ्य सुरक्षा और आजीविका का अवसर जीवन में स्थिरता लाने वाले आधार हैं। योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलना ही उनकी सफलता की वास्तविक कसौटी है।

गांवों में शिक्षा के नए अवसर

ग्रामीण क्षेत्रों में 454 करोड़ रुपये की लागत से 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की पहल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 99 प्रतिशत लाइब्रेरी में पठन-पाठन शुरू हो चुका है।

गांवों में अध्ययन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सीखने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।

महिला रोजगार और किसान सुविधाओं पर ध्यान

कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण में तेजी और उनके संचालन के लिए नीति तैयार करने के निर्देश महिलाओं की रोजगार संबंधी जरूरतों से जुड़े हैं। सुरक्षित आवास की उपलब्धता उन महिलाओं के लिए सहायक हो सकती है, जो नौकरी या प्रशिक्षण के लिए अपने घर से दूर रहती हैं।

वहीं, मंडियों में साफ-सफाई, जलभराव से बचाव और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर कृषि क्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं को संबोधित करता है। बिजली आपूर्ति की शीघ्र बहाली, चौबीसों घंटे शिकायत सुविधा तथा सरकारी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम हैं।

गांवों में अध्ययन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। इससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सीखने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।

विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक

उत्तर प्रदेश में जारी इन पहलों की व्यापकता बताती है कि विकास का लक्ष्य केवल बड़े निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सड़क और लॉजिस्टिक नेटवर्क आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण शिक्षा को मजबूत कर सकती हैं और कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों को सहारा दे सकती हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। जब परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध होंगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, तभी विकास के आंकड़े आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देंगे। यही बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ■

पूर्वांचल में रोजगार की नई बुनाई

योगी की सिल्क क्लस्टर पहल से कारीगरों और युवाओं के लिए खुल सकती हैं संभावनाएं

भदोही, मीरजापुर और वाराणसी में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी; कालीन कारोबार, निर्यात, महिला उद्यमिता और स्थानीय आजीविका को मजबूत करने पर जोर।

पूर्वांचल में रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को नई आर्थिक दिशा देने की पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास नगर (भदोही), मीरजापुर और वाराणसी को सिल्क क्लस्टर के रूप में विकसित करने तथा वाराणसी-विंध्य रीजनल डेवलपमेंट प्लान को जल्द लागू करने की बात कही है। इस पहल का सबसे बड़ा संभावित लाभ स्थानीय रोजगार से जुड़ा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कालीन, रेशम और हस्तशिल्प का कारोबार लंबे समय से कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों की आजीविका का आधार रहा है।

इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण में मुख्यमंत्री ने निर्यातकों, विक्रेताओं और उद्यमियों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कालीन उद्योग के लिए अलग नीति बनाने, हस्तनिर्मित उत्पादों की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने और महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने जैसे सुझाव सामने आए। इन मुद्दों पर सरकार की ओर से संज्ञान लेने का भरोसा दिया गया।



स्थानीय हुनर को स्थानीय रोजगार में बदलने का अवसर

भदोही का कालीन उद्योग अपनी बारीक बुनाई और हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है। मीरजापुर में भी कालीन निर्माण से जुड़ी पारंपरिक दक्षता मौजूद है, जबकि वाराणसी का रेशम और हस्तशिल्प कारोबार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित विकास से उत्पादन, डिजाइन, प्रशिक्षण, पैकेजिंग और विपणन की गतिविधियों को बेहतर ढंग से जोड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं।

इसका लाभ केवल बड़े कारोबारियों तक सीमित न रहकर छोटे बुनकरों, घरेलू कामगारों, रंगाई और फिनिशिंग से जुड़े कारीगरों तथा परिवहन सेवाओं तक पहुंच सकता है। यदि स्थानीय युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण मिले और उन्हें काम से जोड़ने की व्यवस्थित व्यवस्था बने, तो अपने जिले में रोजगार पाने के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे दूसरे शहरों में काम की तलाश में जाने की मजबूरी कम करने में भी मदद मिल सकती है।

कालीन की बुनाई से पैकेजिंग तक रोजगार की पूरी श्रृंखला

हस्तनिर्मित कालीन का निर्माण कई चरणों











से गुजरता है। धागे की तैयारी, डिजाइन बनाना, बुनाई, रंगाई, धुलाई, फिनिशिंग, गुणवत्ता जांच और पैकेजिंग में अलग-अलग प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। कारोबार और ऑर्डर बढ़ने पर इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों के लिए अधिक काम उपलब्ध होने की संभावना रहती है।

इसके अतिरिक्त, निर्यात कारोबार को गति मिलने से माल की ढुलाई, भंडारण, व्यापारिक समन्वय और अन्य सहायक सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है। छोटे उद्यमियों के लिए बेहतर बाजार संपर्क और साझा सुविधाएं उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक रोजगार उपलब्धियों में बदलने के लिए परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी जरूरी होगी।

अलग कालीन नीति से मिल सकती है कारोबार को मजबूती

एक्सपो में उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना से मिले लाभ का उल्लेख करते हुए कालीन उद्योग के लिए अलग नीति बनाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि हस्तनिर्मित कालीनों के निर्माण में लंबा समय और विशेष कौशल लगता है, इसलिए उद्योग की प्रकृति के अनुरूप नीतिगत व्यवस्था आवश्यक है।

यदि इस क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार नीति तैयार होती है और उसके साथ प्रशिक्षण, बाजार विस्तार तथा छोटे कारोबारियों को जरूरी सहयोग मिलता है, तो स्थानीय उत्पादन क्षमता मजबूत हो सकती है। इसका लाभ उन परिवारों तक पहुंचने की संभावना होगी, जिनकी आजीविका पीढ़ियों से इस हुनर पर निर्भर है।

महिला रोजगार को मिले अधिक अवसर

कालीन उद्योग में महिलाओं की भूमिका को अधिक पहचान और अवसर देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। महिला उद्यमी आदर्श पूर्णिमा ने कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीईपीसी) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों के लिए स्थान आरक्षित करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता संबंधी मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच के अवसर मिलें, तो वे उत्पादन के साथ-साथ कारोबार और विपणन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं। इससे परिवारों की आय में योगदान और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका मजबूत होने की संभावना है।

रोजगार के आंकड़ों से मापी जाए पहल की सफलता

सिल्क क्लस्टर और क्षेत्रीय विकास योजना का वास्तविक प्रभाव इस बात से स्पष्ट होगा कि स्थानीय स्तर पर कितने नए रोजगार बनते हैं, कितने युवाओं को प्रशिक्षण के बाद काम मिलता है और कितने कारीगरों को नियमित काम उपलब्ध होता है। महिला कामगारों की भागीदारी, छोटे उद्यमों की वृद्धि और कारीगर परिवारों की आय में बदलाव जैसे संकेतक भी महत्वपूर्ण होंगे।

मुख्यमंत्री की पहल ने पूर्वांचल के पारंपरिक उद्योगों को रोजगार केंद्रित विकास से जोड़ने का अवसर प्रस्तुत किया है। अब जरूरत है कि इस अवसर को जमीन पर परिणामों में बदला जाए, ताकि भदोही, मीरजापुर और वाराणसी की पहचान केवल कालीन और रेशम के उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि ये क्षेत्र स्थानीय हुनर, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका के मजबूत केंद्र भी बन सकें। ■

जब बेटी की उड़ान और बचपन की मुस्कान बने विकास की पहचान

नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में राजस्थान ने महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और पोषण के प्रयासों को रखा सामने



किसी प्रदेश की असली तरक्की केवल ऊंची इमारतों, सड़कों और बड़े निवेश से नहीं मापी जाती। उसकी तस्वीर तब पूरी होती है, जब किसी छोटे से गांव की बेटी पढ़ाई का सपना देख सके, किसी महिला को अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिले और किसी बच्चे का बचपन पोषण, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के भरोसे के साथ आगे बढ़े। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी नीतियों के पीछे यही व्यापक सोच आज देश के विकास विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है।

इसी दृष्टिकोण को नई दिल्ली में आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन में राजस्थान ने भी मजबूती से सामने रखा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री **श्रीमती अन्नपूर्णा देवी** की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में राजस्थान की **उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी** ने सहभागिता की और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, बाल कल्याण, पोषण तथा आंगनवाड़ी सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और नवाचारों को साझा किया।

दिया कुमारी ने राजस्थान की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदेश की हर बेटी को शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। यह सोच केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों को आत्मविश्वास, अवसर और अपने भविष्य को स्वयं आकार देने की क्षमता देने से जुड़ी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण को भी इसी व्यापक बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। जब महिला आर्थिक, सामाजिक और निर्णय लेने के स्तर पर मजबूत होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी तरह बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश आने वाली पीढ़ी की नींव मजबूत करता है।

शिखर सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, योजनाओं और नवाचारों पर विचार-विमर्श हुआ। ऐसे मंचों की खासियत यह है कि राज्यों को अपने अनुभव साझा करने के साथ दूसरे क्षेत्रों में अपनाई जा रही प्रभावी पहलों से सीखने का अवसर भी मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मातृशक्ति को सशक्त बनाने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान की ओर से प्रस्तुत प्रयास इसी दिशा में राज्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं।

दरअसल, महिला और बाल विकास किसी एक विभाग की जिम्मेदारी भर नहीं है। यह उस भविष्य की तैयारी है जिसमें हर बेटी के पास सपने देखने की आजादी हो, **हर महिला के पास आगे बढ़ने का अवसर हो और हर बच्चे को स्वस्थ बचपन का अधिकार मिले।** यही सोच राजस्थान के विकास को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए एक व्यापक और संवेदनशील दिशा देती दिखाई देती है। ■

रोजगार, महिला उद्यमिता और पर्यावरण संतुलन से संवरता उत्तराखंड: विकास की नई दिशा में देवभूमि



हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की पहचान केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है। यह प्रदेश अब रोजगार, महिला उद्यमिता, पर्यटन, निवेश और नवाचार के नए अवसरों के साथ विकास की एक ऐसी राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां स्थानीय संसाधनों को आजीविका का आधार बनाने पर विशेष जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 'देवभूमि से विकास संवाद कॉन्क्लेव' में राज्य की इसी बदलती तस्वीर के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा।

युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार

उत्तराखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां मिली हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती व्यवस्था में निष्पक्षता और योग्यता को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2021 में लगभग 24 हजार रिक्त पदों के बैकलॉग को चुनौती मानते हुए शुरू हुई यह प्रक्रिया युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है।

हालांकि, राज्य की रोजगार नीति का दायरा केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। पर्यटन, होमस्टे, होटल व्यवसाय, टैक्सी संचालन, बागवानी और स्टार्टअप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

महिला शक्ति बनी आर्थिक बदलाव की वाहक

प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ी हैं। उनके हाथों से तैयार स्थानीय उत्पाद अब बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। मिलेट उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्रों, पूजा सामग्री और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास महिलाओं की मेहनत को आर्थिक पहचान देने की पहल है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन और होमस्टे से गांवों में लौटती रौनक

पलायन की चुनौती से जूझते पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन आजीविका का महत्वपूर्ण विकल्प बन रहा है। राज्य में होमस्टे की संख्या लगभग चार हजार से बढ़कर आठ हजार से अधिक होना इस बदलाव का संकेत है। इसी तरह स्टार्टअप की संख्या लगभग 700 से बढ़कर 2,200 तक पहुंची है। आदि कैलाश जैसे नए पर्यटन आकर्षणों और सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों को परिवहन, आवास और आतिथ्य सेवाओं में अवसर मिल रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास भी इसी सोच का हिस्सा है।

विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण

उत्तराखंड के सामने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। 70 प्रतिशत से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र, हिमालयी पारिस्थितिकी, ग्लेशियर और नदियां प्रदेश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, बल्कि देश की पर्यावरणीय सुरक्षा का भी आधार हैं।

मुख्यमंत्री ने विकास के ऐसे मॉडल पर जोर दिया, जिसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी को एक-दूसरे का पूरक माना जाए। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक विकास के लिए विशेष महत्व रखता है।

निवेश से खुलेंगी रोजगार की नई राहें

राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग होने और अन्य 24 से 25 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण यह है कि निवेश का लाभ स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचे।

उत्तराखंड की विकास यात्रा का वास्तविक मूल्यांकन इसी आधार पर होगा कि रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक अवसरों का लाभ दूरस्थ गांवों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है।

देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का संकल्प भी इस विकास दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संदेश स्पष्ट है—उत्तराखंड को आधुनिक अवसरों से जोड़ना है, लेकिन उसकी आत्मा, परंपराओं और प्रकृति की कीमत पर नहीं। यही संतुलन आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और सुरक्षित उत्तराखंड की मजबूत नींव बन सकता है। ■

बुंदेलखंड में बदल रही **विकास की तस्वीर, जमीन से उद्योग** तक बीडा ने पकड़ी रफ्तार

28,874 एकड़ भूमि अर्जन के बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 1,000 एकड़ के एक्टिवेशन एरिया से दिखेगा औद्योगिक बदलाव





बुंदेलखंड की पहचान लंबे समय तक प्राकृतिक चुनौतियों, सीमित औद्योगिक अवसरों और रोजगार के लिए होने वाले पलायन से जुड़ी रही है। लेकिन अब इसी भूभाग पर एक ऐसी औद्योगिक तस्वीर आकार ले रही है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की आर्थिक दिशा बदल सकती है। **बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)** के रूप में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक पहल जमीन पर आगे बढ़ रही है।

01 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बीडा के लिए अनुमोदित **56,662 एकड़ क्षेत्र में से 28,874 एकड़ भूमि का अर्जन पूरा** हो चुका है। यानी औद्योगिक विकास के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता—भूमि—का बड़ा हिस्सा अब उपलब्ध हो चुका है। नवंबर से सितंबर के बीच ही 7,026 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अर्जन और सितंबर में 616 एकड़ की प्रगति इस प्रक्रिया की गति को दर्शाती है।

लेकिन बीडा की कहानी केवल भूमि अर्जन तक सीमित नहीं है। असली बदलाव तब दिखाई देगा, जब अर्जित जमीन पर सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं का नेटवर्क तैयार होगा।

1,000 एकड़ का एक्टिवेशन एरिया बनेगा शुरुआती मॉडल

बीडा के 2,320 एकड़ क्षेत्र को एक्टिवेशन एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके पहले चरण में **1,000 एकड़ क्षेत्र विकसित करने की तैयारी** है। यही वह हिस्सा होगा जहां कागज पर बनी औद्योगिक परिकल्पना धीरे-धीरे जमीन पर दिखाई देगी।

इस क्षेत्र के लिए सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, विद्युत डक्ट और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक भवन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित हैं।

इन विकास कार्यों पर करीब **447.01 करोड़ रुपये** खर्च प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन परियोजनाओं के डीपीआर तैयार किए जा चुके हैं और उन्हें अटल



इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत आगे बढ़ाने की स्वीकृति मिल चुकी है।

औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे नई पहचान

बीडा की योजना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है— **क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास।** डेटा सेंटर और आईटी, केमिकल तथा डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाएं तैयार की जा रही हैं। डेटा सेंटर/आईटी क्लस्टर के लिए 1,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें 810 एकड़ का अर्जन हो चुका है।

यह मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग उद्योगों को एक ही क्षेत्र में आवश्यक साझा सुविधाएं उपलब्ध कराने से निवेशकों के लिए संचालन आसान हो सकता है और स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन, सेवा क्षेत्र तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

निवेशकों की रुचि से बढ़ी उम्मीद

बीडा की संभावनाओं को लेकर विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों की रुचि भी इस परियोजना के भविष्य को लेकर उम्मीद बढ़ाती है। ऑटोमोटिव, डिफेंस, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रमुख समूहों ने निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई है।

यह रुचि इस बात का संकेत है कि बुंदेलखंड को अब केवल पिछड़े क्षेत्र के नजरिए से नहीं, बल्कि **नई औद्योगिक क्षमता वाले क्षेत्र** के रूप में देखा जाने लगा है।

पानी और कनेक्टिविटी— औद्योगिक भविष्य की दो बड़ी जरूरतें

किसी भी बड़े औद्योगिक क्षेत्र की सफलता के लिए जमीन के साथ पानी और कनेक्टिविटी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीडा के लिए **216 एमएलडी जल उपलब्धता** को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

इसके साथ ही एक्सप्रेसवे, रेल संपर्क, मल्टीमॉडल कार्गो पार्क और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएं बीडा को व्यापक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं मजबूत करती हैं।

बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा सवाल—रोजगार और स्थानीय अवसर

किसी भी औद्योगिक परियोजना की सफलता का अंतिम पैमाना केवल निवेश की राशि नहीं, बल्कि यह होता है कि उसका लाभ स्थानीय लोगों तक कितना पहुंचता है। बीडा से उम्मीद यही है कि उद्योगों के साथ प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा परिवहन, वेयरहाउसिंग, होटल, छोटे उद्यम, सर्विस सेक्टर और स्थानीय कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे।

यानी **28,874 एकड़ अर्जित भूमि केवल जमीन का आंकड़ा नहीं है; यह बुंदेलखंड में आर्थिक गतिविधियों के नए भूगोल की शुरुआत का संकेत है।**

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में बीडा को मिला **बेस्ट डिस्प्ले अवॉर्ड** भी इस उभरती औद्योगिक पहचान का एक प्रतीक माना जा सकता है। अब चुनौती यह है कि निवेश की रुचि को धरातल पर परियोजनाओं में बदला जाए और विकास की इस प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं तथा उद्यमियों को सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

अगर यह दिशा लगातार बनी रही, तो आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड की पहचान केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत से नहीं, बल्कि **आधुनिक उद्योग, रोजगार और निवेश के नए केंद्र** के रूप में भी स्थापित हो सकती है। ■

हुनर को नई उड़ान, युवाओं को रोजगार के नए अवसर

PM-SETU: आधुनिक कौशल प्रशिक्षण से उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार होगी नई पीढ़ी



भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इस ताकत को आर्थिक विकास में बदलने के लिए जरूरी है कि युवाओं के पास केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी हों। इसी सोच को आगे बढ़ाने वाली पहल है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई यानी **PM-SETU** योजना, जिसका शुभारंभ अक्टूबर 2025 में किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक बनाकर कौशल विकास व्यवस्था को अधिक प्रासंगिक और रोजगारोन्मुख बनाना है।

पारंपरिक प्रशिक्षण से आधुनिक तकनीकी कौशल तक

तकनीक और उद्योग जगत तेजी से बदल रहे हैं। ऑटोमेशन, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे दौर में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिक होना समय की जरूरत है। **PM-SETU** के तहत देश के 1,000 सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, आधुनिक उपकरणों तक पहुंच बढ़ाना और युवाओं को कार्यस्थल की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करना है।

हब-एंड-स्पोक मॉडल से मजबूत होगा प्रशिक्षण नेटवर्क

योजना में हब-एंड-स्पोक मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से चुनिंदा संस्थानों को प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करते हुए उनसे जुड़े अन्य संस्थानों तक प्रशिक्षण संसाधनों, विशेषज्ञता और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की परिकल्पना है। इससे कौशल विकास के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और अधिक युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

उद्योगों की भागीदारी से बढ़ेगी रोजगारपरक शिक्षा

PM-SETU की खासियत उद्योग जगत की भागीदारी और मांग आधारित प्रशिक्षण पर जोर है। उद्योगों के साथ सहयोग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सरकारी आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) को बदलती कार्यबल जरूरतों से जोड़ने का प्रयास युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता और नई पीढ़ी के कौशलों पर ध्यान भी इस पहल के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

कौशल, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की राह

कौशल विकास का प्रभाव केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहता। बेहतर प्रशिक्षण युवाओं में उद्यमिता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित कर सकता है। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा से शुरुआती परिचय मिलने पर विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव बेहतर ढंग से कर सकते हैं। PM-SETU की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं कितनी प्रभावी बनती हैं, उद्योगों की भागीदारी कितनी मजबूत रहती है और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के कितने वास्तविक अवसर मिलते हैं। यदि इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, तो यह योजना भारत के कौशल विकास तंत्र को नई दिशा देने के साथ युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ■

डिग्री से आगे हुनर की पहचानः उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की पहल

उत्तराखण्ड में जिला स्तर पर बनेगी कौशल विकास की रणनीति, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार से जुड़ाव पर रहेगा जोर



युवाओं के हाथ में प्रमाणपत्र होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस प्रमाणपत्र से रोजगार का रास्ता खुलना उससे भी अधिक जरूरी है। आज उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए और युवाओं को ऐसे कौशल की तलाश है, जिनके सहारे वे अपने भविष्य को मजबूत बना सकें। इन दोनों जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार का प्रस्तावित स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग जगत और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ इसी चुनौती पर चर्चा की गई। उद्देश्य स्पष्ट है—प्रशिक्षण को केवल औपचारिक प्रक्रिया न बनाकर उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं से जोड़ना।

युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानक निर्धारित करने, नियमित मूल्यांकन और थर्ड पार्टी ऑडिट पर जोर दिया गया है।

हर जिले की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण

उत्तराखण्ड के सभी जिलों में रोजगार के अवसर एक जैसे नहीं हैं। इसलिए जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया है। स्थानीय रोजगार संभावनाओं, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं और उद्योगों की मांग का आकलन करके पाठ्यक्रम तय किए जाएं, तो युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जहां रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है, वहां नए कौशल कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत होगी।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी होगी कसौटी

युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानक निर्धारित करने, नियमित मूल्यांकन और थर्ड पार्टी ऑडिट पर जोर दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समन्वय से प्रशिक्षण को व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद मिल सकती है। उभरते कौशल क्षेत्रों की पहचान और सेतु आयोग के अध्ययन का उपयोग भी इस योजना को अधिक प्रासंगिक बनाने की दिशा में अहम है।

हुनर से रोजगार तक का सफर

इस पहल की सफलता का वास्तविक पैमाना प्रशिक्षित युवाओं की संख्या नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाले रोजगार, स्वरोजगार और आगे बढ़ने के अवसर होंगे। उद्योगों की मांग, प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित होता है, तो उत्तराखण्ड का कौशल विकास मॉडल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ युवाओं के भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है। ■

विशेष आलेख

नोएडा की नई उड़ान: सपनों को आकार देता विकास

AI की दुनिया से सौर ऊर्जा तक, बदलते शहर की नई कहानी



शहर भी कभी-कभी अपने लिए एक नया सपना बुनते हैं। ऐसा सपना, जिसमें उद्योगों की रफ्तार हो, युवाओं के लिए अवसर हों, कारोबार के लिए बेहतर माहौल हो और विकास की चमक के साथ प्रकृति के रंग भी सुरक्षित रहें। नोएडा आज इसी तरह के बदलाव की ओर कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है।

28 अक्टूबर 2026 को हुई नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले शहर के इसी बदलते स्वरूप की झलक पेश करते हैं। कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के लिए नए रास्ते तैयार हो रहे हैं, तो कहीं उद्योगों को सहूलियत देने, यातायात को बेहतर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजनाएं आकार ले रही हैं। इन पहलों को केवल कागजों पर दर्ज फैसलों की तरह नहीं, बल्कि आने वाले कल की संभावनाओं के रूप में देखना अधिक प्रासंगिक होगा।

AI सिटी: जहां भविष्य दस्तक दे रहा है

आज दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से तकनीक के इर्द-गिर्द आकार ले रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, स्टार्टअप और डिजिटल सेवाएं रोजगार और कारोबार की नई तस्वीर बना रही हैं। नोएडा में प्रस्तावित AI सिटी-कम-बिजनेस पार्क इसी बदलते दौर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना में AI, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी एवं आईटीईएस, अनुसंधान और कौशल विकास जैसी गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित करने की योजना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यावसायिक परिवेश जहां तकनीकी विचारों को काम करने की जगह मिले, नए उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और हुनरमंद युवाओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुलें।

हालांकि, इन उम्मीदों को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए परियोजना का समयबद्ध विकास और निवेश का धरातल पर उतरना अहम होगा।

उद्योगों की रफ्तार, कारोबार को सहूलियत

नोएडा की पहचान लंबे समय से उद्योग और व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रही है। इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए शहर को ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत है, जो कारोबार को सुगम बनाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें।

सेक्टर-147 में आईटी एवं आईटीईएस गतिविधियों के लिए 68,000 वर्गमीटर भूमि पर आवंटन योजना लाने की सैद्धांतिक मंजूरी और सेक्टर-105 में एकीकृत ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स की योजना को स्वीकृति इसी दिशा से जुड़े कदम हैं।

औद्योगिक इकाइयों के स्थानांतरण शुल्क में 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय भी चर्चा में है। कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं में ऐसी राहत उद्योगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अंततः किसी भी औद्योगिक शहर की असली ताकत केवल वहां मौजूद कंपनियों की संख्या नहीं, बल्कि वहां कारोबार करना कितना सहज है, इससे भी तय होती है।

जब शहर का सामान चलेगा आसान रास्तों पर

शहर की व्यस्त सड़कों पर बढ़ता यातायात केवल लोगों के समय को प्रभावित नहीं करता, बल्कि माल ढुलाई, व्यावसायिक गतिविधियों और पर्यावरण पर भी असर डालता है। ऐसे में



विकास की कहानी तब और अर्थपूर्ण हो जाती है, जब उसकी रोशनी पर्यावरण तक भी पहुंचे। नोएडा प्राधिकरण की परिसंपत्तियों पर लगभग 15 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना इसी सोच से जुड़ी है।

नोएडा के लिए तैयार सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस योजना में माल परिवहन, वितरण व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य परिवहन लागत कम करना, जाम का दबाव घटाना और संबंधित व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

यदि योजना के प्रस्ताव प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो उद्योगों से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक, शहर की आर्थिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। क्योंकि तेज रफ्तार शहर वही होता है, जहां केवल लोग ही नहीं, जरूरी सामान भी समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सके।

विकास की धूप, ऊर्जा का नया रास्ता

विकास की कहानी तब और अर्थपूर्ण हो जाती है, जब उसकी रोशनी पर्यावरण तक भी पहुंचे। नोएडा प्राधिकरण की परिसंपत्तियों पर लगभग 15 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना इसी सोच से जुड़ी है।

सीवेज शोधन संयंत्रों, जलाशयों और बहुस्तरीय कार पार्किंग स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे बिजली खर्च में बचत और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस परियोजना से अगले 25 वर्षों में लगभग पांच लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है।

यह पहल एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचार सामने रखती है—शहर का विकास केवल अधिक निर्माण करने में नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में भी है।

नियमों में बदलाव, रोजमर्रा के कामों में आसानी

किसी शहर की प्रगति बड़े प्रोजेक्ट्स से जरूर पहचानी जाती है, लेकिन आम लोगों और कारोबारियों के लिए छोटी-छोटी प्रक्रियाओं की सहजता भी उतनी ही मायने रखती है।

बोर्ड बैठक में मॉडल भवन विनियम-2026 को नोएडा में लागू करने की स्वीकृति, कुछ वाणिज्यिक संपत्तियों के उप-पट्टे से जुड़ी सुविधाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रक्रियागत बदलावों को मंजूरी दी गई। मोबाइल टावर और राइट ऑफ वे से संबंधित अनुमतियों की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का फैसला भी इसी क्रम में महत्वपूर्ण है।

इन बदलावों से संबंधित कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने की संभावना है। वहीं, पांच प्रतिशत आबादी भूखंडों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए मास्टर प्लान-2031 में संशोधन का प्रस्ताव किसानों से संबंधित एक अहम विषय को सामने लाता है। इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनसामान्य से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के बाद शासन को संदर्भित किए जाने का प्रावधान है।

नोएडा का अगला अध्याय: उम्मीदों से उपलब्धियों तक

नोएडा की विकास यात्रा एक ऐसे मोड़ पर है, जहां आधुनिक तकनीक, औद्योगिक विस्तार, बेहतर परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। ये सभी एक-दूसरे से जुड़े पहलू हैं और मिलकर ही किसी शहर के भविष्य को आकार देते हैं।

हालिया बोर्ड बैठक के फैसले इस दिशा में नई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। AI सिटी का विचार भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था से जुड़ता है, लॉजिस्टिक्स प्लान शहर की व्यावसायिक गति को बेहतर बनाने की उम्मीद जगाता है और सौर ऊर्जा की पहल विकास के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी को जोड़ती है।

लेकिन योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आएगा, जब वे जमीन पर उतरेंगी और लोगों को उनका लाभ महसूस होगा। बेहतर रोजगार के अवसर, सरल प्रक्रियाएं, सुविधाजनक शहरी व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण ही वे कसौटियां हैं, जिन पर विकास की सफलता को परखा जाएगा।

नोएडा की कहानी अब केवल एक शहर के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि उस भविष्य की तलाश भी है, जहां प्रगति के साथ सुविधा, तकनीक के साथ अवसर और विकास के साथ जिम्मेदारी आगे बढ़े।

क्योंकि शहर का असली भविष्य उसकी इमारतों की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उन संभावनाओं में बसता है, जिन्हें वह अपने लोगों के लिए खोलता है। ■



यीडा में उद्योगों की नई उड़ान: 3,155 करोड़ के निवेश से खुलेंगे रोजगार के हजारों द्वार

95 एकड़ भूमि पर आकार लेंगी औद्योगिक परियोजनाएं, मेडिकल डिवाइस से फार्मा तक निवेश की नई संभावनाएं

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र निवेश, विनिर्माण और रोजगार के नए अवसरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यहां 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किए जाने के साथ लगभग 3,155 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। करीब 95 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं से 9,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

यह पहल केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने की व्यापक संभावनाएं भी समेटे हुए है। नए उद्योगों के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला और विभिन्न सहायक सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों में काम करने वाले लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों और सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को भी मिल सकता है।

परंपरागत उद्योगों के साथ आधुनिक विनिर्माण पर जोर

प्रस्तावित निवेश की विशेषता इसका विविध औद्योगिक स्वरूप है। जारी एलओआई के अनुसार, 11 कंपनियां सेक्टर-8डी के जनरल इंडस्ट्री क्षेत्र में, जबकि आठ कंपनियां सेक्टर-29 में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। सेक्टर-29 में तीन



कंपनियां अपैरल पार्क, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क और चार जनरल इंडस्ट्री क्षेत्र में निवेश करेंगी। इसके अतिरिक्त एक कंपनी मेडिकल डिवाइस पार्क, तीन कंपनियां मिक्स्ड लैंड यूज और दो कंपनियां प्रस्तावित फार्मा पार्क में निवेश करेंगी।

यह विविधता यीडा के औद्योगिक विकास को व्यापक आधार प्रदान कर सकती है। परिधान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा फार्मास्यूटिकल उद्योगों की संभावनाएं प्रदेश को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। विशेषीकृत औद्योगिक पार्कों के विकास से कंपनियों को अपनी जरूरतों के अनुरूप भूमि और औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराने में भी मदद मिल सकती है।

निवेश से रोजगार तक, विकास की व्यापक संभावना

किसी भी औद्योगिक परियोजना की वास्तविक सफलता का आकलन केवल निवेश की राशि से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव से भी किया जाता है। प्रस्तावित 9,000 से अधिक रोजगार अवसर इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के साथ तकनीकी कर्मचारियों, मशीन ऑपरेटरों, प्रबंधन कर्मियों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, वास्तविक रोजगार सृजन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उत्पादन शुरू होने पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। यीडा क्षेत्र में सामने आए ये प्रस्ताव इसी व्यापक औद्योगिक विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। बेहतर संपर्क मार्गों, औद्योगिक सुविधाओं और निवेशोन्मुख नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आधार

यीडा में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का असर आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देने की संभावना है। उद्योगों को कच्चे माल, पैकेजिंग, परिवहन, रखरखाव और अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। इससे छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं। स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी दक्षता विकसित करने के अवसर मिलें, तो रोजगार का लाभ क्षेत्र के अधिक लोगों तक पहुंच सकता है।

आने वाले समय में इन निवेश प्रस्तावों का वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय पर स्थापित होती हैं, उत्पादन शुरू करती हैं और रोजगार के वादों को धरातल पर उतारती हैं। फिलहाल, 25 कंपनियों को जारी एलओआई यीडा के औद्योगिक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि प्रस्तावित निवेश योजनाबद्ध ढंग से साकार होते हैं, तो यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसरों को मजबूत आधार दे सकता है। ■



खेती को नई दिशा, किसानों को नई उम्मीद

पीएम धन-धान्य कृषि योजना का एक वर्ष: 100 जिलों में कृषि विकास की मजबूत होती नींव

भारत की कृषि व्यवस्था को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है कि विकास की योजनाएं खेतों तक पहुंचें और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप परिणाम दें। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। 11 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई इस योजना ने अपने पहले वर्ष में देश के 100 चयनित जिलों में कृषि विकास को गति देने के लिए जिला स्तर पर सुनियोजित कार्ययोजनाओं और प्रगति की निगरानी का आधार तैयार किया है।

स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि विकास पर जोर

भारत में कृषि की परिस्थितियां हर क्षेत्र में अलग-अलग हैं। कहीं सिंचाई की चुनौती है, तो कहीं उत्पादकता बढ़ाने, कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत चयनित जिलों में जिला कार्ययोजनाओं का निर्माण इस बात का संकेत है कि कृषि विकास को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

आंकड़ों से विकास की दिशा तय करने की पहल

योजना की एक प्रमुख विशेषता संकेतकों पर आधारित निगरानी व्यवस्था है। इससे विभिन्न जिलों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का आकलन करने और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। प्रभावी निगरानी से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं।

समन्वित प्रयासों से मजबूत होगा कृषि क्षेत्र

कृषि विकास के लिए केवल एक योजना पर्याप्त नहीं होती। सिंचाई, कृषि ऋण, भंडारण, तकनीक, फसल विविधीकरण और किसानों को बाजार से जोड़ने जैसे प्रयासों के बीच तालमेल आवश्यक है। जिला कार्ययोजनाओं के आधार पर विभिन्न विभागों और विकास कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय किसानों के लिए अधिक व्यापक लाभ का रास्ता खोल सकता है।

योजना का पहला वर्ष आगे की यात्रा के लिए आधार तैयार करने का अवसर है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि योजनाबद्ध प्रयास किसानों की आय, कृषि उत्पादकता, संसाधनों की उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना ठोस सुधार ला पाते हैं।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना की वास्तविक उपलब्धि तभी होगी, जब जिला स्तर पर बनी विकास की रूपरेखा खेतों में बदलाव और किसानों के जीवन में खुशहाली के रूप में दिखाई देगी। यही लक्ष्य भारतीय कृषि को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ■



खेतों की विरासत से फ्रांस तक पहुंचा कालानमक का स्वाद

सिद्धार्थनगर के 'बुद्धा डिलाइट्स' ने परंपरा में नवाचार जोड़कर बनाई वैश्विक बाजार में पहचान

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में 200 बिजनेस इंक्वायरी, करीब चार करोड़ रुपये की संभावित कारोबारी रुचि और फ्रांस से 20 लाख रुपये का कन्फर्म ऑर्डर।

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की पहचान सदियों से कालानमक चावल की विशिष्ट सुगंध और स्वाद से जुड़ी रही है। अब यही पारंपरिक कृषि उत्पाद आधुनिक उद्यमिता के सहारे एक नए रूप में बाजार तक पहुंच रहा है। तीन पीढ़ियों से कालानमक की खेती करने वाले परिवार की विरासत को डॉ. अजय कुमार रावत ने कुकीज़ जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलकर नई कारोबारी संभावनाओं का रास्ता खोला है।

ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में उनकी इकाई 'बुद्धा डिलाइट्स' को मिली प्रतिक्रिया इस बदलाव की ओर संकेत करती है। आयोजन के दौरान इकाई को 200 बिजनेस इंक्वायरी प्राप्त हुईं, जिनसे करीब चार करोड़ रुपये की संभावित कारोबारी संभावनाएं बनीं। वहीं, फ्रांस के एक खरीदार से 50 हजार कुकीज़ की आपूर्ति का कन्फर्म ऑर्डर मिला, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है।

जब पारंपरिक चावल बना आधुनिक स्वाद का हिस्सा

डॉ. रावत के परिवार के लिए कालानमक केवल एक कृषि उपज नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सहेजी जा रही विरासत है। राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट करने और प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बावजूद उनका जुड़ाव अपनी मिट्टी से बना रहा। उन्होंने कालानमक को चावल के पारंपरिक स्वरूप से आगे ले जाने का विचार विकसित किया और खाद्य प्रसंस्करण की बारीकियां सीखने के लिए पुणे से कुकरी एवं बेकरी में डिप्लोमा हासिल किया।

लगातार प्रयोगों के बाद वर्ष 2024 में बुद्धा डिलाइट्स की स्थापना हुई। इसके माध्यम से कालानमक काजू कुकीज़, एरोमैटिक ब्राउन राइस कुकीज़, ड्राई फ्रूट शुगर-फ्री कुकीज़ और गुड़ से बनी कुकीज़ जैसे उत्पाद तैयार किए गए। इस प्रयोग ने स्थानीय कृषि उत्पाद को नए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की संभावना प्रस्तुत की।

ट्रेड शो में कारोबार और उपभोक्ताओं का मिला साथ

यूपीआईटीएस-2026 के दौरान बुद्धा डिलाइट्स ने प्रत्यक्ष उपभोक्ता बिक्री के रूप में 4.70 लाख रुपये का कारोबार किया। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक पूछताछ और फ्रांस से मिले ऑर्डर ने उद्यम के लिए नए बाजारों के द्वार खोले हैं। कंपनी का वार्षिक टर्नओवर लगभग तीन करोड़ रुपये बताया गया है।

वित्तीय सहयोग से विस्तार की उम्मीद

उद्यम के विस्तार के लिए डॉ. रावत ने 'एक जनपद एक व्यंजन पोषण वित्त योजना' के अंतर्गत 50 लाख रुपये का ऋण लिया है। इस पर संबंधित विभाग के माध्यम से 10 लाख रुपये की मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय संसाधनों का यह सहयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बाजार तक पहुंच मजबूत करने में उपयोगी हो सकता है।

डॉ. रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूपीआईटीएस जैसे मंच स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं।

स्थानीय उत्पाद, वैश्विक संभावनाएं

बुद्धा डिलाइट्स की कहानी बताती है कि कृषि विरासत को नवाचार, कौशल और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़कर नए व्यावसायिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि, संभावित कारोबारी पूछताछ को वास्तविक बिक्री में बदलना, गुणवत्ता बनाए रखना और समय पर निर्यात आपूर्ति करना आगे की महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी।

सिद्धार्थनगर के खेतों में पीढ़ियों से उगाया जा रहा कालानमक अब नए उत्पाद के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की राह पर है। यह सफर स्थानीय कृषि को मूल्य संवर्धन से जोड़ने और पारंपरिक उपज को आधुनिक उद्यमिता के माध्यम से नई पहचान दिलाने की एक उल्लेखनीय मिसाल है। ■

पहाड़ की रसोई से एक करोड़ के कारोबार तक: सरस फूड फेस्टिवल ने दिखाई ग्रामीण महिलाओं के हुनर की ताकत

उत्तराखंड के पारंपरिक स्वाद, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को मिला बड़ा बाजार; 7 दिनों में स्वयं सहायता समूहों का 1.01 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार





गांव की रसोई में तैयार होने वाली सेब की चटनी, पहाड़ के खेतों में उगने वाला राजमा और महिलाओं के हाथों से बने पारंपरिक व्यंजन अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं हैं। देहरादून में आयोजित सरस फूड फेस्टिवल-2026 ने इन उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के साथ ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता को नई पहचान दी। सात दिवसीय आयोजन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने कुल **1,01,00,692 रुपये का कारोबार** किया। यह आंकड़ा केवल बिक्री का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि ग्रामीण हुनर को बाजार से जोड़ने की संभावनाओं का भी संकेत है।

5 से 11 अक्टूबर तक देहरादून के रेंजर ग्राउंड में आयोजित इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों और देश के 17 राज्यों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने पारंपरिक खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प, हैंडलूम और अन्य स्थानीय वस्तुओं का प्रदर्शन एवं बिक्री की। अलग-अलग क्षेत्रों के स्वाद और शिल्प ने एक ही परिसर में भारत की विविध लोकसंस्कृति की झलक प्रस्तुत की।

मोरी की सेब चटनी से पहाड़ी व्यंजनों तक, हर स्टॉल की अपनी कहानी

फेस्टिवल में उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र से आई जय मातृ शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी खास रही। आत्मनिर्भर क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी इन महिलाओं ने पतियुड के पकौड़े, सिद्दू, सेलू और उड़द की दाल के पकौड़ों जैसे पारंपरिक व्यंजनों से लोगों को पहाड़ के स्वाद से परिचित कराया।

मोरी की सेब चटनी भी आकर्षण का केंद्र





सरस फूड फेस्टिवल-2026 का संदेश स्पष्ट है—जब ग्रामीण महिलाओं के हुनर को बाजार, पहचान और अवसर मिलते हैं, तो गांव की रसोई से निकला उत्पाद भी बड़े कारोबार की राह बना सकता है।



बनी। महिलाओं द्वारा तैयार यह स्थानीय उत्पाद लगभग 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था। इसके साथ राजमा, लाल चावल, काला तिल और भट्ट की दाल जैसे पारंपरिक कृषि उत्पादों को भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया। हिलान्स के माध्यम से बिक्री की पहल ने स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने की संभावनाओं को मजबूत किया। समूह के मल्टीग्रेन बिस्किट भी लोगों की रुचि का हिस्सा बने।

117 समूहों को स्टॉल, स्थानीय हुनर को मिला मंच

उत्तराखंड के 117 स्वयं सहायता समूहों को फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों के स्टॉल आवंटित किए गए। इनमें देहरादून जिले के 30 से अधिक समूहों की महिलाएं भी शामिल रहीं। फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और लाइव फूड स्टॉल के माध्यम से प्रतिभागियों को ग्राहकों से सीधे जुड़ने और अपने उत्पादों की मांग समझने का अवसर मिला।

ऐसे आयोजन ग्रामीण उद्यमियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं के सामने अक्सर विपणन, पैकेजिंग और व्यापक ग्राहक वर्ग तक पहुंच बनाने की चुनौती रहती है। एक साझा मंच उन्हें अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने, ग्राहकों की पसंद जानने और भविष्य के कारोबार की संभावनाएं तलाशने का अवसर देता है।

लखपति दीदी से आगे बढ़ने की उम्मीद

फेस्टिवल की नोडल अधिकारी अनीता पंवार के अनुसार, ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन देहरादून के तत्वावधान में आयोजित इस सात दिवसीय आयोजन ने समूहों की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराया। उनके मुताबिक, एक करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती व्यावसायिक भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने इसे लखपति दीदी से आगे बढ़कर बड़े उद्यम खड़े करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर बताया।

जय मातृ शक्ति समूह की अध्यक्ष मंजू राणा ने भी ऐसे आयोजनों को ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने वाला मंच बताया। उनके अनुसार, जो उत्पाद पहले गांव और आसपास के क्षेत्रों में बिकते थे, उन्हें अब बड़े शहर के ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।

परंपरा से उद्यमिता तक का सफर

सरस फूड फेस्टिवल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहां परंपरागत व्यंजन और स्थानीय उत्पाद केवल सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बनकर नहीं रहे, बल्कि आजीविका और कारोबार की संभावनाओं से भी जुड़े। ग्रामीण महिलाओं का कौशल, स्थानीय संसाधन और सामूहिक प्रयास मिलकर ऐसे उद्यमों की नींव रख सकते हैं, जो परिवारों की आय बढ़ाने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दें। ■



हरियाणा से स्वीडन तक विकास की नई साझेदारी

निवेश, तकनीक और रोजगार के वैश्विक अवसरों की दस्तक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 4,000 करोड़ रुपये के एलओआई, गुरुग्राम–स्टॉकहोम सहयोग और स्मार्ट सिटी से लेकर डिजिटल सुरक्षा तक साझेदारी का विस्तार

निर्माणशाला टाइम्स

औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं तब आकार लेती हैं, जब किसी राज्य की युवा शक्ति, बुनियादी ढांचा और निवेश के अनुकूल वातावरण वैश्विक तकनीक एवं पूंजी से जुड़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 14 से 17 अक्टूबर 2026 तक का स्वीडन दौरा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया। इस यात्रा का केंद्र केवल विदेशी निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि औद्योगिक साझेदारी, कौशल विकास, आधुनिक शहरी नियोजन और तकनीकी नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास को व्यापक आधार देना भी रहा।

4,000 करोड़ रुपये के एलओआई से निवेश की उम्मीदें

दौरे के दौरान हरियाणा सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच कुल 4,000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी गई। इनमें 3,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इनसे आधुनिक लॉजिस्टिक्स, खुदरा कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि, वास्तविक निवेश और रोजगार का आकलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद ही हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन दौसा से मुलाकात कर शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश तथा प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया।

इनोवेशन डे पर 'मेक इन इंडिया–मेड विद स्वीडन' का संदेश

इंडिया–स्वीडन इनोवेशन डे 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ने नवाचार को दोनों देशों के साझा भविष्य का आधार बताया। उन्होंने



द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और हरियाणा में स्वीडिश कंपनियों की मौजूदगी का उल्लेख किया। गुरुग्राम में आइकिया की लगभग 3,500 करोड़ रुपये की एकीकृत परियोजना, झज्जर की मेट सिटी में कार्ल गुस्ताफ विनिर्माण संयंत्र तथा फरीदाबाद में एबीबी की विनिर्माण इकाई इस औद्योगिक संबंध के प्रमुख उदाहरण हैं। गुरुग्राम में स्वीडिश शिक्षा संस्था कुनस्काप्सकोलन की मौजूदगी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की एक और कड़ी है।

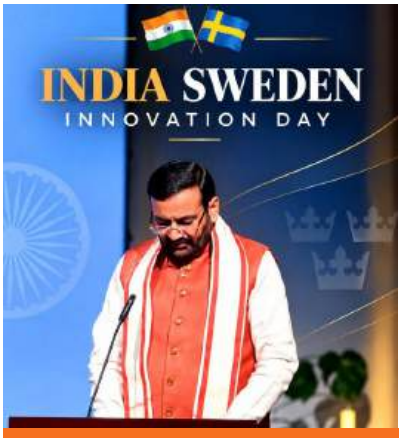
स्मार्ट शहरों से हरित विकास तक

स्टॉकहोम में भारत–स्वीडन सतत शहरी विकास राउंडटेबल के दौरान स्मार्ट मोबिलिटी, जल संरक्षण और ग्रीन एनर्जी में सहयोग पर जोर दिया गया। हरियाणा के दस नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी और केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास प्रस्तावित पांच नए शहर स्वीडिश कंपनियों के लिए संभावित अवसर प्रस्तुत करते हैं।

गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच सिटी-टू-सिटी सहयोग की पहल से शहरी प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ विकास के अनुभव साझा करने का रास्ता खुल सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वीडन के हैमरबी स्यो-स्ताद और वेस्टर्न हार्बर जैसे शहरी विकास मॉडलों से सीखने की आवश्यकता भी रेखांकित की।

डिजिटल सुरक्षा और आधुनिक तकनीक पर नजर

स्टॉकहोम में एरिक्सन और ट्रूकॉलर के मुख्यालयों के दौरे के दौरान संचार तकनीक, आपातकालीन परिस्थितियों में रोबोटिक्स के उपयोग और स्पैम एवं धोखाधड़ी वाली कॉलों से सुरक्षा पर जानकारी ली गई। एनवैक की आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन भी शहरी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी समाधान तलाशने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा।



स्टॉकहोम में भारत–स्वीडन सतत शहरी विकास राउंडटेबल के दौरान स्मार्ट मोबिलिटी, जल संरक्षण और ग्रीन एनर्जी में सहयोग पर जोर दिया गया। हरियाणा के दस नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी और केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास प्रस्तावित पांच नए शहर स्वीडिश कंपनियों के लिए संभावित अवसर प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक साझेदारी का लाभ युवाओं तक पहुंचे

स्वीडन में बसे सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद में भी निवेश, रोजगार और युवा सशक्तीकरण के विषय सामने आए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 18 ड्राई पोर्ट्स का उल्लेख करते हुए लॉजिस्टिक्स और व्यापार में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया। उन्होंने स्वीडिश कंपनियों से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही, प्रतिनिधियों को कुरुक्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में आमंत्रित किया।

हरियाणा के लिए इस यात्रा की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरें, स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिले और नई तकनीक आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाए। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, कौशल प्रशिक्षण और संतुलित शहरीकरण पर ध्यान दिया जाए, तो भारत–स्वीडन साझेदारी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ विकास को अधिक टिकाऊ बनाने में भी योगदान दे सकती है। ■



खबर की रफ्तार नहीं, सच्चाई की विश्वसनीयता है पत्रकारिता की असली ताकत

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता का मीडिया से आह्वान—भ्रामक सूचनाओं को चुनौती दें, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएं और जनहित के सवालों को बनाएं प्राथमिकता

डिजिटल दौर में खबरें कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार सूचना प्रवाह के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता तक पहुंचने वाली जानकारी कितनी सच्ची, विश्वसनीय और जनहित से जुड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार फर्जी सामग्री और सोशल मीडिया पर फैलती अपुष्ट सूचनाओं के बीच पत्रकारिता की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शिमला में 'जैम्स ऑफ हिमाचल अवॉर्ड्स-2026' समारोह में इसी जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकारिता को स्वस्थ लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बताया।

न्यूज़ 09 चैनल द्वारा आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा कि मीडिया की भूमिका केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। वह जनचेतना जगाने, समाज की समस्याओं को सामने लाने और सरकार तथा नागरिकों के बीच संवाद का सेतु बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कमजोर वर्गों की आवाज बने मीडिया

राज्यपाल ने मीडिया संस्थानों की सफलता को केवल प्रसारण की पहुंच या पाठकों-दर्शकों की संख्या से आंकने के बजाय समाज के प्रति उनके योगदान से जोड़ने की बात कही। उनके अनुसार, कमजोर वर्गों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना, जनशिकायतों को मंच देना और सकारात्मक सामाजिक पहलों को सामने लाना पत्रकारिता की सार्थकता के महत्वपूर्ण आधार हैं।

यह दृष्टिकोण मीडिया को केवल सूचना देने वाले माध्यम से आगे बढ़ाकर सामाजिक बदलाव का सहभागी बनाता है। जब किसी दूरदराज गांव की समस्या, किसी जरूरतमंद परिवार की आवाज या किसी नागरिक की उपलब्धि प्रमुखता से सामने आती है, तो पत्रकारिता का वास्तविक जनहितकारी स्वरूप दिखाई देता है।

एआई के दौर में तथ्य-जांच सबसे जरूरी

राज्यपाल ने आगाह किया कि खबर सबसे पहले देने की होड़ में सही जानकारी की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। भ्रामक सूचनाएं, अपुष्ट खबरें और एआई से तैयार फर्जी सामग्री जनविश्वास को प्रभावित करने के साथ सामाजिक सौहार्द के लिए भी चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में तथ्यों की पुष्टि, संतुलित प्रस्तुति और जिम्मेदार भाषा मीडिया की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने सनसनी के स्थान पर सत्य, नकारात्मकता के बजाय समाधान और विभाजनकारी विचारों के स्थान पर संवाद को महत्व देने का संदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि जिम्मेदार पत्रकारिता का अर्थ समस्याओं को छिपाना या आलोचना से बचना नहीं, बल्कि तथ्यों और जनहित के आधार पर सवाल उठाना है।

समाज के जरूरी मुद्दों पर नजर

युवाओं में नशे की प्रवृत्ति, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, साइबर अपराध और सामाजिक सौहार्द जैसे विषयों पर मीडिया की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं की सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के साथ उनके क्रियान्वयन से जुड़े सवाल उठाना भी जवाबदेही मजबूत करने का माध्यम है।

समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। न्यूज 09 के प्रबंध निदेशक अजय ठाकुर ने उनका स्वागत किया।

राज्यपाल का संदेश स्पष्ट है—स्वतंत्रता पत्रकारिता की ताकत है और जिम्मेदारी उसकी विश्वसनीयता। जब मीडिया अंतिम व्यक्ति की आवाज बने, गलत सूचनाओं को चुनौती दे और जनहित को प्राथमिकता दे, तभी वह लोकतंत्र को अधिक जागरूक, संवेदनशील और मजबूत बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है। ■

सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर कम, डिजिटल मंच पर 939 सुविधाएं

सेवा सेतु से 38 विभाग जुड़े, 16 हजार से अधिक सेवा केंद्रों का नेटवर्क; तकनीक के सहारे आम नागरिक तक पहुंच रहीं शासकीय सेवाएं



छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं तक पहुंच का तरीका बदलने की कोशिश अब डिजिटल मंच के जरिए आगे बढ़ रही है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों से लेकर विवाह पंजीयन और गुमास्ता लाइसेंस तक, अनेक सेवाओं के लिए एक ही मंच पर आवेदन की सुविधा नागरिकों के समय और श्रम को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित 'सेवा सेतु' का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है।

19 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सेवा सेतु पर प्रदेश के 38 विभागों की 939 सेवाएं उपलब्ध हैं। इनके संचालन के लिए 16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। अब तक ऑनलाइन प्राप्त 55 लाख 13 हजार 672 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है, जबकि 21,582 अधिकारी-कर्मचारी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। ये आंकड़े डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के प्रयास का दायरा दिखाते हैं।

सेवा सेतु की उपयोगिता केवल आवेदन ऑनलाइन करने तक सीमित नहीं है। डिजिटल व्यवस्था आवेदन को संबंधित विभाग और अधिकारी तक पहुंचाने, उसकी स्थिति पर नजर रखने तथा कार्यवाही को व्यवस्थित करने में भी सहायक हो सकती है।

इस व्यवस्था का महत्व उन लोगों के लिए विशेष रूप से बढ़ जाता है, जिन्हें किसी प्रमाण पत्र या दूसरे सरकारी काम के लिए बार-बार कार्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले नागरिकों के लिए दूरी, यात्रा खर्च और समय अक्सर बड़ी चुनौती होते हैं। ऑनलाइन आवेदन और स्थानीय सेवा केंद्रों की मदद से इन परेशानियों को कम करने की संभावना बनती है। जिन लोगों को डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, वे भी सेवा केंद्रों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा सेतु की उपयोगिता केवल आवेदन ऑनलाइन करने तक सीमित नहीं है। डिजिटल व्यवस्था आवेदन को संबंधित विभाग और अधिकारी तक पहुंचाने, उसकी स्थिति पर नजर रखने तथा कार्यवाही को व्यवस्थित करने में भी सहायक हो सकती है। इससे जवाबदेही बढ़ाने और नागरिकों को सेवाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है।

हालांकि, किसी भी डिजिटल व्यवस्था की वास्तविक सफलता केवल सेवाओं की संख्या या प्राप्त आवेदनों से नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध निराकरण और नागरिकों के अनुभव से तय होती है। आवेदन की स्थिति स्पष्ट रहना, तकनीकी बाधाओं का समाधान और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की सक्रियता इसके लाभ को और व्यापक बना सकती है।

सेवा सेतु इसी दिशा में डिजिटल तकनीक और जनसुविधा के बीच सेतु बनाने का प्रयास है। यदि सेवाओं का क्रियान्वयन सरल, भरोसेमंद और जवाबदेह बना रहता है, तो सरकारी कामकाज की जटिलता घटाने के साथ नागरिकों का समय बचाने में भी यह व्यवस्था प्रभावी भूमिका निभा सकती है। ■

सरकारी योजनाओं के सहारे आत्मनिर्भरता की उड़ान,

भारती रावत ने मुर्गी पालन से बदली परिवार की आर्थिक तस्वीर

आरईएपी परियोजना की 75 हजार रुपये की सब्सिडी और ब्याजमुक्त ऋण से खड़ा हुआ उद्यम; हर उत्पादन चक्र में 50 से 55 हजार रुपये की आय से ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को मिली नई दिशा

ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं तब बदलाव का प्रभावी माध्यम बनती हैं, जब आर्थिक सहायता उन्हें अपना काम शुरू करने और परिवार की आय बढ़ाने का अवसर देती है। हरिद्वार जिले के लालढांग क्षेत्र स्थित चमारिया गांव की भारती रावत की कहानी इसी बदलाव को सामने लाती है। सरकारी सहायता, ब्याजमुक्त ऋण और तकनीकी सहयोग के सहारे उन्होंने मुर्गी पालन को आजीविका का साधन बनाया है। वर्ष 2025 में शुरू हुआ उनका ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म अब परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रहा है।

35 वर्षीय भारती के सामने अपना उद्यम शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। ऐसे में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली आरईएपी (रूरल एंटरप्राइज एक्सेलेरेशन प्रोजेक्ट) परियोजना के तहत मिली 75 हजार रुपये की सब्सिडी ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक से 1.60 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण लेकर उन्होंने पोल्ट्री शेड का निर्माण कराया। इस वित्तीय सहयोग से घर के पास उपलब्ध कृषि भूमि पर अपना व्यवसाय शुरू करने का रास्ता खुला।

सहायता से शुरू हुआ काम, मेहनत से बढ़ा भरोसा

आज भारती की यूनिट में प्रत्येक उत्पादन चक्र में लगभग 2,200 ब्रॉयलर चूजों का पालन



किया जाता है। वह सात उत्पादन चक्र पूरे कर चुकी हैं। प्रत्येक चक्र में करीब 40 से 45 दिन लगते हैं और इससे उन्हें लगभग 50 से 55 हजार रुपये की आय होती है। यह आय परिवार की जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक मजबूती बढ़ाने में मदद कर रही है।

भारती की उपलब्धि योजनाओं के प्रभाव का एक व्यावहारिक उदाहरण है। सब्सिडी ने शुरुआती निवेश का बोझ कम किया, जबकि ब्याजमुक्त ऋण ने बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता दी। इससे वह केवल सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थी नहीं रहीं, बल्कि अपना उद्यम संचालित करने वाली महिला उद्यमी के रूप में आगे बढ़ीं।

तकनीकी सहयोग ने बाजार तक पहुंच आसान बनाई

मुर्गी पालन में उत्पादन के साथ चूजों की उपलब्धता, आहार, टीकाकरण और बिक्री की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है। भारती के परिवार को हरियाणा के करनाल स्थित कल्याण हैचरी से इन क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। इसमें वैक्सीनेटेड चूजे, पशु आहार, परिवहन, पशु चिकित्सकीय परामर्श और तैयार पक्षियों के विपणन में सहायता शामिल है। डिजिटल माध्यम से मांग के अनुसार बिक्री और बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था बाजार से जुड़ने में सहायक है।

एक महिला की पहल, दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता

भारती रावत ने सहायता और मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनकी कहानी बताती है कि योजनाओं का असर केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रहता। सही मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ाव मिलने पर सहायता स्वरोजगार, आत्मविश्वास और परिवार की आर्थिक भागीदारी में बदल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहल महिलाओं को अपने हुनर और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। भारती का अनुभव इस बात को रेखांकित करता है कि सरकारी योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता तब सामने आती है, जब उनका लाभ जमीन पर एक टिकाऊ आजीविका और आत्मनिर्भरता का आधार बन सके। ■

छत्तीसगढ़ के पर्यटन में अब चमकेगी स्थानीय हुनर की रोशनी, गांवों तक पहुंचेगी समृद्धि





चित्रकोट से मैनपाट तक पर्यटन विकास की नई उम्मीद; स्थानीय युवाओं, महिलाओं, हस्तशिल्पियों और जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने पर जोर

छत्तीसगढ़ के किसी गांव में बनी बांस की कलाकृति हो, किसी जनजातीय परिवार के घर का पारंपरिक भोजन या पीढ़ियों से सहेजा जा रहा लोकनृत्य—इनमें प्रदेश की ऐसी पहचान छिपी है, जिसे किसी पर्यटन पुस्तिका में पूरी तरह समेटना आसान नहीं। यही विरासत अब स्थानीय लोगों की आजीविका के नए अवसरों से जुड़ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तावित मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन इसी संभावना को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाना नहीं, बल्कि पर्यटन से पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उन परिवारों तक पहुंचाना भी है, जिनकी संस्कृति और जीवनशैली छत्तीसगढ़ की असली पहचान हैं।

मिशन की मूल भावना 'पर्यटन से समृद्धि' है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये की मूल मिशन निधि प्रस्तावित की गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, केंद्रीय योजनाओं और विभागीय समन्वय से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक संसाधन जुटाने की कार्ययोजना भी बनाई गई है। इस निवेश की अहमियत तब और बढ़ेगी, जब इससे स्थानीय लोगों के लिए नियमित काम, छोटे कारोबार और सम्मानजनक आय के अवसर बनेंगे।

जब स्थानीय हुनर बनेगा परिवार की ताकत

मिशन में 1,000 नए पर्यटन उद्यमी तैयार करने और 250 महिला स्व-सहायता समूहों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 600 आतिथ्य एवं पर्यटक सहायता कर्मियों तथा 500 टूर गाइड और फ्रंटलाइन कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इन अवसरों से स्थानीय युवा पर्यटक मार्गदर्शक, होमस्टे संचालक, परिवहन सेवा प्रदाता या आतिथ्य क्षेत्र के कर्मी बन सकते हैं। महिला समूह पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के जरिए अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

इस बदलाव का मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण है। जब किसी कारीगर की बनाई वस्तु पर्यटकों तक पहुंचती है, तो उसकी कला को पहचान मिलती है। जब किसी ग्रामीण परिवार के घर में पर्यटक ठहरते हैं, तो स्थानीय भोजन, परंपरा और आतिथ्य भी आजीविका का हिस्सा बनते हैं। इससे नई पीढ़ी को पारंपरिक हुनर सहेजने और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिल सकती है।

पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं, गांवों में नए अवसर

चित्रकोट जलप्रपात, मैनपाट, सिरपुर, हसदेव बांगो और राजिम जैसे स्थलों को विकसित करने की योजना है। बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पार्किंग, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा जैसी सुविधाएं पर्यटकों के साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी उपयोगी होंगी। चार प्रमुख और 15 मिनी पर्यटन सर्किट विकसित करने तथा 12 हजार अतिरिक्त कमरों की आवास क्षमता तैयार करने का लक्ष्य भी प्रस्तावित है। बहुभाषी वेबसाइट, मोबाइल एप और डिजिटल बुकिंग जैसी सुविधाएं पर्यटकों की यात्रा को सरल बना सकती हैं।

लेकिन विकास की असली कसौटी केवल पर्यटकों की संख्या नहीं होगी। जरूरी है कि स्थानीय परिवारों को प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और उद्यम शुरू करने में व्यावहारिक सहयोग मिले। पर्यटन से होने वाली कमाई का लाभ गांवों तक पहुंचे और स्थानीय संस्कृति केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर न रह जाए।

मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय विरासत की मौलिकता और गरिमा बनाए रखने के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। यदि इन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का पर्यटन विकास केवल प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीर नहीं बदलेगा—यह स्थानीय परिवारों के लिए बेहतर आजीविका, युवाओं के लिए नए रास्ते और अपनी विरासत पर गर्व करने का अवसर भी बन सकता है। ■

जहां गांव की उम्मीद है, वहां बैंकिंग का भरोसा है

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक : वित्तीय समावेशन से आर्थिक आत्मनिर्भरता तक

किसी प्रदेश की आर्थिक प्रगति को केवल बड़े शहरों की चमक से नहीं मापा जा सकता। असली तस्वीर तब सामने आती है, जब गांव का किसान अपनी अगली फसल के लिए आत्मविश्वास के साथ तैयारी करता है, कोई युवा अपने गांव में ही रोजगार की संभावना तलाशता है, कोई छोटा कारोबारी अपने व्यवसाय को विस्तार देने का सपना देखता है और कोई महिला अपनी मेहनत को आय के अवसर में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाती है।

इन सपनों के बीच **वित्तीय पहुंच और भरोसेमंद बैंकिंग व्यवस्था** की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसी व्यापक सोच के साथ **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के साथ अपने जुड़ाव को नई दिशा दे रहा है। 1 मई 2025 से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन से गठित यह बैंक एकीकृत बैंकिंग व्यवस्था के रूप में सामने आया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैंक का मिशन किसानों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों, महिलाओं और बैंकिंग सुविधाओं से अपेक्षाकृत कम जुड़े वर्गों तक सुलभ तथा तकनीक-सक्षम वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है।

बैंकिंग से आगे—ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साझेदारी

ग्रामीण भारत में बैंक की भूमिका केवल जमा और निकासी तक सीमित नहीं है। यहां बैंकिंग का संबंध खेती, स्वरोजगार, छोटे कारोबार, महिला उद्यमिता और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ता है।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग-अलग क्षेत्रों

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक | Corporate Spotlight

- ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी बैंकिंग पर केंद्रित व्यापक संस्थागत उपस्थिति
- किसानों, महिलाओं, कारीगरों और छोटे व्यवसायों पर विशेष मिशन फोकस
- डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा
- 1 मई 2025 से एकीकृत नई बैंकिंग पहचान
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित सरकारी स्वामित्व वाला अनुसूचित बैंक

की आर्थिक गतिविधियां अलग हैं—कहीं कृषि प्रमुख है, कहीं पशुपालन, कहीं छोटे उद्योग और कहीं स्थानीय व्यापार। ऐसे में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक नेटवर्क स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का माध्यम बन सकता है।

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की कहानी केवल एक बैंक की कहानी नहीं, बल्कि **ग्रामीण भारत में बदलती आर्थिक आकांक्षाओं की कहानी** भी है।

किसान के खेत से छोटे कारोबार तक

किसान के लिए वित्तीय सुविधा खेती की तैयारी का हिस्सा है। ग्रामीण दुकानदार के लिए कारोबार बढ़ाने का साधन। युवा के लिए स्वरोजगार की शुरुआत का आधार और छोटे उद्यमी के लिए विस्तार की संभावना। जब इन जरूरतों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाता है, तो उसका प्रभाव केवल एक ग्राहक तक सीमित नहीं रहता। एक सफल छोटा व्यवसाय परिवार की आय बढ़ा सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और स्थानीय बाजार में आर्थिक गतिविधि को गति दे सकता है।

इसीलिए ग्रामीण बैंकिंग को केवल वित्तीय सेवा के रूप में नहीं, बल्कि **स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास के एक महत्वपूर्ण आधार** के रूप में देखा जाना चाहिए।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की नई तस्वीर

ग्रामीण भारत में महिला अब केवल परिवार की आर्थिक व्यवस्था की सहभागी नहीं, बल्कि अनेक स्थानों पर उद्यम और आय-सृजन की सक्रिय भागीदार भी बन रही है।

स्वयं सहायता समूह, छोटे घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और अन्य स्वरोजगार गतिविधियां महिलाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रही हैं। बैंकिंग से जुड़ाव इन गतिविधियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का आधार दे सकता है। जब एक महिला अपनी बचत, आय और आर्थिक निर्णयों को व्यवस्थित तरीके से संभालती है, तो उसका प्रभाव परिवार से आगे समुदाय तक जाता है।

डिजिटल युग में ग्रामीण बैंकिंग

ग्रामीण ग्राहक भी तेजी से डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की आधिकारिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था में इंटरनेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। बैंक वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय उत्पादों, डिजिटल सेवाओं, सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता पर भी जोर देता है।

यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की ग्रामीण बैंकिंग केवल शाखा तक पहुंच की कहानी नहीं होगी। यह **सुविधा, तकनीक, सुरक्षा और वित्तीय जागरूकता** के संतुलन की कहानी होगी।

एक बड़ा नेटवर्क, एक साझा विश्वास

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों और बड़ी संख्या में शाखाओं की सूची उपलब्ध है। इसका व्यापक भौगोलिक जुड़ाव बैंक को ग्रामीण और अर्ध-शहरी ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाने की महत्वपूर्ण क्षमता देता है।

बैंक के लिए यह नेटवर्क केवल भौगोलिक विस्तार नहीं, बल्कि उन लाखों आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर है जो प्रदेश की जमीनी अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं।

नई पहचान, नई संभावनाएं

2025 में हुए एकीकरण के बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने अपनी नई संस्थागत पहचान को और मजबूत करने का अवसर है। एकीकृत बैंकिंग व्यवस्था, तकनीक, वित्तीय साक्षरता और ग्रामीण जरूरतों की समझ को साथ लेकर बैंक अपनी विकास यात्रा को और व्यापक बना सकता है।

और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है— **विश्वास।**

क्योंकि बैंकिंग की अंतिम कसौटी केवल यह नहीं कि कितने खाते खुले या कितने लेन-देन हुए। असली कसौटी यह है कि बैंकिंग सुविधा ने कितने लोगों को अपने आर्थिक भविष्य के बारे में अधिक आत्मविश्वास से सोचने का अवसर दिया।

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में गांवों की भूमिका निर्णायक है। और गांवों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने में वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इसी बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच एक ऐसी संस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जहां बैंकिंग का अर्थ केवल धन का लेन-देन नहीं, बल्कि अवसर, भरोसा और आर्थिक भागीदारी से जुड़ता है। ■

वेलमन फाउंडेशन
मानव सेवा से सामाजिक बदलाव की नई इबारत

सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व के संकल्प के साथ बेहतर समाज के निर्माण की पहल

समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल आर्थिक विकास और आधुनिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि इस बात से भी होता है कि विकास की रोशनी समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक कितनी पहुंच रही है। जब कोई संस्था मानवीय संवेदनाओं को अपना आधार बनाकर सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसकी पहल समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाती है। इसी व्यापक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में संचालित **वेलमन फाउंडेशन** एक सार्थक सामाजिक पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प प्रस्तुत करता है।

सेवा ही सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व

सामाजिक संस्थाओं की भूमिका केवल सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना भी होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंद परिवारों का सहयोग और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने जैसे विषय किसी भी संवेदनशील समाज की प्राथमिकताएं हैं।

वेलमन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के लिए ये क्षेत्र समाज के साथ जुड़ने और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण परिवेश के बीच बेहतर सामाजिक समन्वय स्थापित करना आज समय की आवश्यकता है।

संवेदना से सशक्तीकरण तक का सफर

आज जरूरत केवल तात्कालिक राहत की नहीं, बल्कि ऐसे प्रयासों की है जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दें। जरूरतमंदों को सहयोग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता, महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन तथा युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना बदलाव की मजबूत नींव बन सकता है।

वेलमन फाउंडेशन के लिए भी सामाजिक सहभागिता, पारदर्शिता और निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से ऐसे उद्देश्यों को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण दिशा हो सकती है।

बेहतर समाज, साझा जिम्मेदारी

सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति या संस्था के प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता से संभव होता है। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत और प्रशासन के सहयोग से जनकल्याण की पहल अधिक प्रभावी बन सकती है।

वेलमन फाउंडेशन का सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण इसी व्यापक सोच को रेखांकित करता है कि मानव सेवा केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी है। ■

एक समस्या से खड़ा किया स्टार्टअप, मां-बेटे की उद्यमशीलता ने पकड़ी उड़ान

झांसी की अनुराधा मेहरोत्रा ने बेटे के विचार को कारोबार में बदला, 'हॉस्टल्स नियर मी' को 10 लाख की ग्रांट से विस्तार की नई उम्मीद



उद्यमिता की शुरुआत हमेशा किसी बड़े निवेश या शानदार दफ्तर से नहीं होती। कई बार इसकी नींव रोजमर्रा की किसी परेशानी में छिपी होती है। झांसी की अनुराधा मेहरोत्रा और उनके बेटे आर्यमन की कहानी इसका उदाहरण है। कॉलेज के दिनों में हॉस्टल तलाशने में हुई परेशानी ने एक ऐसे डिजिटल स्टार्टअप का विचार दिया, जो आज कई शहरों के विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। खास बात यह है कि इस विचार को कारोबार में बदलने के सफर में मां ने केवल प्रेरक की नहीं, बल्कि एक उद्यमी और परिचालन प्रमुख की भूमिका निभाई।

समस्या को अवसर में बदलने की सोच

दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के सामने रहने की सुरक्षित और उपयुक्त जगह तलाशना अक्सर बड़ी चुनौती होता है। हॉस्टल की अधूरी जानकारी, विकल्पों की कमी और अनजान शहर में सही ठिकाना चुनने की चिंता विद्यार्थियों के साथ उनके परिवारों को भी परेशान करती है। आर्यमन ने इसी समस्या का समाधान खोजने का विचार अपनी मां से साझा किया। अनुराधा ने इस विचार में एक व्यावहारिक कारोबारी संभावना देखी। यहीं से 'हॉस्टल्स नियर मी' की शुरुआत हुई।

यह पहल उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को सामने लाती है—बाजार की वास्तविक जरूरत को पहचानना और उसके अनुरूप समाधान तैयार करना। किसी समस्या को केवल व्यक्तिगत अनुभव मानकर छोड़ देने के बजाय उसे अनेक लोगों के काम आने वाली सेवा में बदलना ही इस स्टार्टअप की मूल सोच है।

मां ने संभाली कारोबार की कमान

अनुराधा मेहरोत्रा ने स्टार्टअप की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनका योगदान इस बात का उदाहरण है कि महिला उद्यमिता केवल किसी व्यवसाय की शुरुआत करने तक सीमित नहीं,



बल्कि उसके संचालन, विकास और विस्तार की जिम्मेदारी उठाने में भी दिखाई देती है।

मां-बेटे की यह साझेदारी पारिवारिक विश्वास को व्यावसायिक सहयोग में बदलती है। आर्यमन का विचार और अनुराधा की सक्रिय भागीदारी मिलकर उस उद्यमशील दृष्टिकोण को सामने लाते हैं, जिसमें समस्या की पहचान, योजना, प्रबंधन और लगातार सुधार महत्वपूर्ण होते हैं।

सरकारी अनुदान से विस्तार की राह

वर्ष 2024 में कंपनी के रूप में पंजीकृत 'हॉस्टल्स नियर मी' बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के इनक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की 'स्टार्ट इन यूपी' पहल के अंतर्गत इसके लिए 10 लाख रुपये की ग्रांट स्वीकृत हुई, जिसकी पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। स्टार्टअप के लिए ऐसी आर्थिक सहायता केवल पूंजी उपलब्ध कराने तक सीमित महत्व नहीं रखती। इससे तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाने, प्लेटफॉर्म के विकास और अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। किसी शुरुआती उद्यम के लिए संस्थागत सहयोग बाजार में अपनी उपयोगिता साबित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है।

छह शहरों में बनी पहचान, अब मोबाइल ऐप की तैयारी

फिलहाल यह प्लेटफॉर्म वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थियों को हॉस्टल खोजने में मदद कर रहा है। झांसी के साथ लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर, इंदौर और मेरठ जैसे शहरों में भी इसका उपयोग हो रहा है। स्टार्टअप की योजना नए फीचर जोड़ने और भविष्य में मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने की है।

इस विस्तार के साथ अवसर और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती हैं। हॉस्टल संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, सेवा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों का भरोसा किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की दीर्घकालीन सफलता के लिए अहम होंगे। इन पहलुओं पर मजबूत काम स्टार्टअप को केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि उपयोगी और भरोसेमंद सेवा के रूप में स्थापित कर सकता है।

उद्यमिता का असली अर्थ केवल अपना कारोबार खड़ा करना नहीं, बल्कि किसी जरूरत को समझकर ऐसा समाधान तैयार करना है, जिससे दूसरों का जीवन आसान हो। झांसी का यह स्टार्टअप इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है— जहां एक मां का विश्वास, बेटे का विचार और तकनीक की मदद मिलकर एक नई कारोबारी संभावना गढ़ रहे हैं।

स्थानीय विचार, व्यापक कारोबारी संभावना

'हॉस्टल्स नियर मी' की कहानी झांसी से उभरती उस नई उद्यमशील सोच की ओर संकेत करती है, जिसमें स्थानीय अनुभव डिजिटल समाधान का आधार बनते हैं। ऐसे स्टार्टअप विद्यार्थियों की समस्या हल करने के साथ तकनीकी कौशल, प्रबंधन और रोजगार से जुड़े अवसरों की संभावनाएं भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि, उनका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितनी प्रभावी सेवा देते हैं और समय के साथ अपने कारोबार को किस तरह टिकाऊ बनाते हैं।

अनुराधा मेहरोत्रा और आर्यमन की पहल का सकारात्मक पक्ष यही है कि उन्होंने एक सामान्य परेशानी में कारोबारी संभावना देखी और उसे आगे बढ़ाने का साहस दिखाया। यह कहानी महिलाओं की उद्यमिता, पीढ़ियों के बीच सहयोग और छोटे शहरों से उभरते नवाचार की क्षमता को एक साथ सामने लाती है। ■

विशेष

बिहार में उद्योगों की नई सुबह

रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

मुजफ्फरपुर का मेगा लेदर एवं फुटवियर क्लस्टर बना औद्योगिक बदलाव की नई उम्मीद, 2030 तक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य



सैयद मोहम्मद अली

बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने की दिशा में अब उद्योग, निवेश और रोजगार को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। लंबे समय से बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वाले युवाओं के लिए अपने ही प्रदेश में अवसर उपलब्ध कराना इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। इसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र महवल में मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन बिहार के औद्योगिक भविष्य की एक अहम पहल के रूप में देखा जा सकता है। करीब 140.95 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना स्थानीय संसाधनों, उद्यमशीलता और कौशल को बाजार की जरूरतों से जोड़ने की संभावनाएं प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अक्टूबर को इस क्लस्टर का उद्घाटन करते हुए वर्ष 2030 से पहले बिहार से बाहर मजदूरी करने जाने वाले लोगों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य सामने रखा। राज्य में लगभग 12 लाख लोगों के बाहर जाकर मजदूरी करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने उद्योगों के व्यापक नेटवर्क के विकास पर जोर दिया। इस लक्ष्य की सफलता केवल नए औद्योगिक परिसरों के निर्माण से नहीं, बल्कि उनमें नियमित उत्पादन, पर्याप्त निवेश और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने से तय होगी।



साझा सुविधा केंद्र से छोटे उद्यमों को मिल सकता है सहारा

लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज जैसे क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के सामने उत्पादन, डिजाइन, गुणवत्ता, मशीनरी और विपणन की चुनौतियां रहती हैं। साझा सुविधा केंद्र इन जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो सकता है। इससे उद्यमियों को आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच बनाने और अपने उत्पादों को बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने का अवसर मिल सकता है। औद्योगिक इकाइयों को शेड और भूमि आवंटन पत्र देना भी इस दिशा में व्यावहारिक कदम है।

उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) के बीच समझौता इस परियोजना को कौशल विकास और डिजाइन विशेषज्ञता से जोड़ने की संभावना रखता है। यदि प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक मांग के अनुरूप तैयार किया जाए, तो युवाओं के लिए रोजगार के साथ स्वरोजगार के रास्ते भी खुल सकते हैं।

निवेश की नीति से आगे, जमीन पर उत्पादन की चुनौती

बिहार सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत पहल कर



रही है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। यह निवेशकों की मांगों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने का संकेत है। हालांकि, निवेश का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब प्रस्ताव कारखानों में बदलें, उत्पादन शुरू हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो।

मुजफ्फरपुर में भूमि उपलब्धता, बेहतर परिवहन, हवाई संपर्क और ड्राई पोर्ट जैसी सुविधाओं के विकास की योजनाएं भी औद्योगिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इससे स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग, भंडारण और विपणन को गति मिलने के साथ दूसरे राज्यों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान बनाने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

डेटा सेंटर से डिजिटल अर्थव्यवस्था तक की तैयारी

बिहार के औद्योगिक भविष्य की परिकल्पना पारंपरिक विनिर्माण तक सीमित नहीं है। सरकार ने वर्ष 2030 से पहले 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं हैं। डिजिटल आधारभूत संरचना का विस्तार आईटी सेवाओं, तकनीकी दक्षता और सहायक व्यवसायों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। इसके लिए विश्वसनीय बिजली, मजबूत डिजिटल नेटवर्क, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक निवेश

औद्योगिक विकास तभी व्यापक बदलाव लाएगा, जब स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं को उद्यमिता के अवसर, छोटे कारोबारियों को बाजार और किसानों को उद्योगों से जुड़ने का रास्ता मिलेगा। भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विस्तार के दौरान प्रभावित परिवारों के हितों, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।

आवश्यक होंगे।

इसके साथ अगले पांच वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। बिजली, सड़क, परिवहन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता मिलकर ही निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं।

विकास का असली पैमाना: स्थानीय लोगों की भागीदारी

बिहार में उद्योगों के विस्तार का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे रोजगार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संभावना बनती है। राज्य सरकार की उद्यमिता सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता देने की पहल भी युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर, पटना और गया के बीच तेज रेल संपर्क विकसित करने की योजना क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे सकती है।

औद्योगिक विकास तभी व्यापक बदलाव लाएगा, जब स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं को उद्यमिता के अवसर, छोटे कारोबारियों को बाजार और किसानों को उद्योगों से जुड़ने का रास्ता मिलेगा। भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विस्तार के दौरान प्रभावित परिवारों के हितों, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है।

मुजफ्फरपुर का मेगा लेदर एवं फुटवियर क्लस्टर बिहार के सामने एक अवसर प्रस्तुत करता है—ऐसा अवसर, जिसमें उद्योगों की स्थापना के साथ रोजगार, कौशल और स्थानीय समृद्धि को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अब इस पहल की असली सफलता उत्पादन शुरू होने, निवेश के धरातल पर उतरने और बिहार के युवाओं को अपने घर के करीब सम्मानजनक आजीविका मिलने से आंकी जाएगी। ■



कार्बन फाइनेंस से संवरेगा झारखंड का भविष्य, पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कार्बन बाजार बना विकास का नया अवसर, किसानों और जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने की दिशा में झारखंड की पहल

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के सामने आज एक ओर पर्यावरण संरक्षण की चुनौती है, तो दूसरी ओर ग्रामीण एवं जनजातीय आबादी की आजीविका को मजबूत बनाने की आवश्यकता। ऐसे में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने के लिए कार्बन बाजार एक नई संभावना बनकर उभर रहा है। यह केवल प्रदूषण कम करने की आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जंगलों, खेतों, जलस्रोतों और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम भी बन सकता है।

इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रांची में 'Leveraging Carbon Market for a Climate Resilient Jharkhand' विषय पर हितधारक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कार्बन वित्त के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि वानिकी, भूमि पुनर्स्थापन और ग्रामीण विकास को गति देने की संभावनाओं पर व्यापक विमर्श हुआ।

पर्यावरण संरक्षण में आर्थिक अवसर की नई राह

कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजीव कुमार ने कार्बन ट्रेडिंग को पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय आजीविका संवर्धन का महत्वपूर्ण साधन बताया। ISRO के आंकड़ों के आधार पर राज्य में लगभग 69 प्रतिशत भूमि क्षरण की चुनौती का उल्लेख करते हुए उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि पुनर्स्थापन और बायोगैस जैसे उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता रेखांकित की।

इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी तक सीमित रखने के बजाय इसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, किसानों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

किसानों की आय से जुड़ेगा कार्बन बाजार

कार्बन वित्त की सबसे बड़ी संभावनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण शामिल है। कृषि वानिकी, टिकाऊ खेती और भूमि सुधार जैसी गतिविधियों के माध्यम से कार्बन अवशोषण बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक मूल्यांकन और निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने तथा उनके माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाने की संभावना बनती है।

नाबार्ड के प्रतिनिधि राकेश सिन्हा ने वित्तीय योजनाओं के जरिए किसानों और ग्रामीण समुदायों तक कार्बन वित्त पहुंचाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। यह व्यवस्था प्रभावी रूप लेती है तो छोटे किसानों और जनजातीय परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं।

तकनीक से होगी प्राकृतिक संपदा की निगरानी

कार्यशाला में CLIMATEX द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। उपग्रह चित्रों और वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से जैवभार एवं मिट्टी में संचित कार्बन का आकलन करने वाले डिजिटल मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (dMRV) उपकरण का प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ झारखंड के लिए 'Climate Hazard Mapping for Jharkhand' रिपोर्ट जारी की गई।

वैज्ञानिक आंकड़ों और डिजिटल तकनीक का यह उपयोग भविष्य में परियोजनाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

साझेदारी से तैयार होगा जलवायु अनुकूल विकास मॉडल

कार्यशाला में नाबार्ड, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, GIZ, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, JSLPS, PRADAN, Social Alpha, हिंडाल्को और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तकनीकी सत्रों में सरकारी योजनाओं को कार्बन बाजार से जोड़ने, CSR, प्रभाव निवेश तथा मिश्रित वित्त के जरिए जलवायु अनुकूल परियोजनाओं का विस्तार करने पर विचार किया गया।

झारखंड की इस पहल का वास्तविक महत्व तभी सामने आएगा, जब कार्बन बाजार से मिलने वाले आर्थिक अवसरों का लाभ सीधे किसानों, वनवासी और जनजातीय समुदायों तक पहुंचे। जंगलों का संरक्षण, उपजाऊ भूमि की बहाली और ग्रामीण आय में वृद्धि यदि एक ही विकास प्रक्रिया के हिस्से बन सकें, तो कार्बन वित्त झारखंड के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ समावेशी आर्थिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है। ■

अमृत कूप

अतीत की जल विरासत से भविष्य की प्यास बुझाने की तैयारी

गाजियाबाद में 10 प्राचीन कुओं को मिलेगा नया जीवन, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के आधुनिक मॉडल से जुड़ेंगे पारंपरिक जलस्रोत





पानी की हर बूंद का महत्व उस शहर से बेहतर कौन समझ सकता है, जहां तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के बीच भूजल का संरक्षण बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गाजियाबाद में अब इस चुनौती का समाधान तलाशने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ अपनी पुरानी जल विरासत की ओर भी लौटने की पहल हुई है। जिला प्रशासन ने डाबर इंडिया लिमिटेड और पूर्वा फाउंडेशन के सहयोग से 'अमृत कूप' अभियान शुरू किया है। इसके पहले चरण में 10 पुराने कुओं का पुनर्जीवन किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी नालियों में बहने के बजाय जमीन के भीतर पहुंचकर भूजल स्तर सुधारने में योगदान दे सके।

800 तालाबों से कुओं तक पहुंचा संरक्षण का प्रयास

गाजियाबाद में जल संरक्षण की दिशा में तालाबों के पुनर्जीवन का काम पहले से चल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ के अनुसार, जिले में करीब 800 तालाब चिह्नित किए गए हैं, जिनमें लगभग 200 का जीर्णोद्धार हो चुका है। अब इसी सोच को पारंपरिक कुओं तक विस्तार दिया जा रहा है। अभियान के तहत करीब 180 पुराने और अनुपयोगी कुओं की पहचान की गई है। शुरुआती प्रयोग के तौर पर दो कुओं को विकसित भी किया गया था।

छतों का पानी पहुंचेगा धरती की गहराई तक

अमृत कूप की खासियत केवल पुराने कुओं की मरम्मत नहीं, बल्कि उन्हें वर्षा जल संचयन की उपयोगी व्यवस्था से जोड़ना है। मकानों की छतों से बारिश का पानी पाइप के जरिये फिल्टर चैंबर तक पहुंचेगा। निस्पंदन के बाद इसे कुओं में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिल सकेगा। सुराना, रावली, दिदौली, दबाना, चुड़ियाला, फरीदनगर के दो कुओं, फफराना, सारा और सहजनपुर में ये कार्य प्रस्तावित हैं।

उद्योगों की भागीदारी से संरक्षण को नई राह

डाबर इंडिया लिमिटेड के सीएसआर सहयोग से 10 कुओं के पुनर्जीवन पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक कुएं पर करीब दो लाख रुपये की लागत प्रस्तावित है। भूगर्भ जल विभाग तकनीकी मार्गदर्शन देगा, जबकि पूर्वा फाउंडेशन कुओं के चयन, पुनर्जीवन और स्थानीय सहभागिता में सहयोग करेगा।

मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने पारंपरिक जलस्रोतों को फिर उपयोगी बनाने और औद्योगिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। डाबर इंडिया के सीएसआर प्रमुख व्यास आनंद, पूर्वा फाउंडेशन के संस्थापक रोहित सांगवान तथा भूगर्भ जल विभाग की नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल सहित संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अमृत कूप की सफलता इस बात से तय होगी कि ये संरचनाएं कितनी प्रभावी ढंग से बारिश का पानी सहेज पाती हैं और भूजल पुनर्भरण में कितना योगदान देती हैं। यदि तकनीकी निगरानी और नियमित रखरखाव के साथ यह मॉडल सफल होता है, तो गाजियाबाद की पुरानी जल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का नया आधार बन सकती है। ■

बागवानों की राह होगी आसान, गांवों की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत

टिक्कर-जरोल-गाहन सड़क के लिए 36 करोड़ रुपये मंजूर, गुणवत्तापूर्ण निर्माण से बागवानी को मिलेगा संबल

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि किसानों और बागवानों की मेहनत को बाजार तक पहुंचाने वाली जीवनरेखा है। सेब की पेटियों को मंडियों तक पहुंचाने में लगने वाला समय, परिवहन की लागत और रास्तों की स्थिति बागवानों की आमदनी पर सीधा असर डालती है। ऐसे में टिक्कर-जरोल-गाहन सड़क के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति रामपुर क्षेत्र के बागवानी आधारित ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण कदम है।



रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। यह निर्देश इसलिए अहम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की मजबूती और टिकाऊपन स्थानीय लोगों की सुविधा के साथ-साथ उनकी आजीविका से भी जुड़ा है। बेहतर सड़क बनने से सेब उत्पादकों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे परिवहन संबंधी परेशानियां कम करने और बागवानी कारोबार को गति देने में मदद मिल सकती है।

दूध और सेब के दामों से आय बढ़ाने की कोशिश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार का जोर किसानों, पशुपालकों और बागवानों की आमदनी बढ़ाने पर है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में दूध का खरीद मूल्य 32 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर लगभग दोगुना किया गया है। इससे दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। यह बढ़ोतरी उन बागवानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी उपज के उचित मूल्य और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच बेहतर आय की उम्मीद रखते हैं।

इन पहलों का व्यापक महत्व यह है कि गांवों में होने वाली कृषि, पशुपालन और बागवानी से अर्जित आय स्थानीय बाजारों, छोटे कारोबारों और ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को भी सहारा देती है। जब गांव में पैसा पहुंचता है, तो उसका लाभ केवल उत्पादक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी गतिविधियां बढ़ती हैं।

विकास योजनाओं में गांवों की आवाज को जगह

मुख्यमंत्री ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पाट गांव में आयोजित 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याएं सुनने की बात कही। गांवों से प्राप्त सुझावों और आवश्यकताओं के आधार पर योजनाओं को बजट में शामिल करने का यह दृष्टिकोण स्थानीय जरूरतों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है। अपेक्षित राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सके, तो इसका लाभ प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।

रामपुर क्षेत्र के लिए सड़क, बागवानी और ग्रामीण संवाद से जुड़ी ये पहलें विकास की एक ऐसी तस्वीर सामने रखती हैं, जिसमें गांवों की जरूरतें केंद्र में हैं। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि स्वीकृत सड़क परियोजना समय पर और टिकाऊ गुणवत्ता के साथ पूरी हो, ताकि पहाड़ों में मेहनत करने वाले बागवानों को उसका वास्तविक लाभ मिल सके। ■



किसानों के हक से लेकर युवाओं के रोजगार तक, ग्रेटर नोएडा के विकास को नई दिशा

145वीं बोर्ड बैठक के फैसलों में जमीन, जनसुविधा, सुरक्षा और औद्योगिक भविष्य पर जोर

ग्रेटर नोएडा में विकास की अगली तस्वीर केवल नई सड़कों और औद्योगिक इमारतों तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में किसान के अधिकार, युवाओं का रोजगार, गांवों की आबादी से जुड़े सवाल और उद्योगों के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं भी हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले इसी व्यापक सोच की ओर संकेत करते हैं। किसानों के मुआवजे और आबादी भूखंड से जुड़े मुद्दों पर राहत, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण केंद्र की तैयारी तथा बिजली और पुलिस व्यवस्था के विस्तार जैसे निर्णय क्षेत्र के विकास को जनहित से जोड़ने की कोशिश हैं।

किसानों को राहत, पुराने मुआवजे की उम्मीद

भूमि देने वाले किसानों के हितों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमति से जमीन देने वालों को लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में लिया गया। निर्धारित शर्तों के तहत 5,725 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर वाला विकल्प चुनने वाले भू-स्वामियों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ मिलेगा। वहीं, 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण या क्रय से प्रभावित उन किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जिन्हें अब तक यह लाभ नहीं मिल पाया था। लंबे समय से मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए यह फैसला राहत की उम्मीद जगाता है।

आबादी भूखंड की पात्रता में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। परिवार की परिभाषा में सास-ससुर को शामिल करने से पात्रता संबंधी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। यह संशोधन उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है, जहां भूमि हस्तांतरण के कारण परिवार की बहुओं को आबादी भूखंड के लाभ से वंचित होना पड़ सकता था।

लीज बैक और पुनर्वास की राह होगी आसान

ग्रामीण आबादी की जमीन के लीज बैक मामलों में ब्याज माफी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर ब्याज और पट्टा निरस्तीकरण जैसी शर्तें कई मामलों में परेशानी का कारण बनती रही हैं। प्रस्तावित राहत के लिए शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी। साथ ही, किसानों के हिस्से का निर्धारण कर लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्ट्री से एनएच-9 तक लिंक रोड निर्माण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी में 5.48 एकड़ भूमि पर भूखंडों की लीज डीड कराने को भी मंजूरी दी गई है। इसकी प्रक्रिया में पात्रता और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा तथा लीज डीड का खर्च प्राधिकरण वहन करेगा।

कौशल प्रशिक्षण से रोजगार तक का रास्ता

युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए ईकोटेक-1 में करीब आठ एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र विकसित करने की योजना है। यहां तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण के साथ भाषा प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। हॉस्टल और प्लेसमेंट सेल जैसी व्यवस्थाएं युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयारी का अवसर दे सकती हैं। भूमि आवंटन एमएसएमई विभाग की सहमति के बाद किया जाएगा।

सुरक्षा और बिजली ढांचे को मजबूती

ईकोटेक-1 एक्सटेंशन में पुलिस थाना स्थापित करने के लिए 3,957 वर्गमीटर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के बीच पुलिस ढांचे का सुदृढ़ीकरण कर्मचारियों, उद्यमियों और आसपास के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, ईकोटेक-10 के मौजूदा 132 केवी विद्युत उपकेंद्र को 220 केवी स्तर पर उन्नत करने की योजना है। लगभग 226 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए 8,945 वर्गमीटर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इससे ईकोटेक-10, ईकोटेक-11, घंघोला और मायचा सहित आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती बिजली मांग पूरी करने में मदद मिल सकती है।

फैसलों की असली कसौटी उनका क्रियान्वयन

इन निर्णयों में किसानों के अधिकारों से लेकर रोजगार और औद्योगिक सुविधाओं तक विकास के कई पहलू शामिल हैं। हालांकि, मुआवजे का वास्तविक भुगतान, लीज डीड का समयबद्ध निष्पादन, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और बिजली परियोजना का धरातल पर उतरना ही इनकी सफलता तय करेगा। यदि घोषणाएं प्रभावी क्रियान्वयन में बदलती हैं, तो ग्रेटर नोएडा का विकास केवल औद्योगिक विस्तार नहीं, बल्कि किसान परिवारों की सुरक्षा, युवाओं की आकांक्षाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी बन सकता है। ■

अंतरिक्ष तकनीक से बदलेगी बिहार के विकास की तस्वीर, अब समस्याओं के समाधान में विज्ञान की होगी बड़ी भूमिका

बाढ़ प्रबंधन से खेती और जनसेवाओं तक, आधुनिक तकनीक को जमीन पर उतारने की पहल









बिहार के सामने विकास की चुनौतियाँ जितनी व्यापक हैं, उनके समाधान के लिए आधुनिक तकनीक की संभावनाएँ भी उतनी ही बड़ी हैं। बाढ़, जल प्रबंधन, कृषि नियोजन और तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों के बीच अंतरिक्ष आधारित तकनीक राज्य के विकास को नई दिशा दे सकती है। खास बात यह है कि अब वैज्ञानिक नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं और तकनीकी संस्थानों तक सीमित रखने के बजाय आम लोगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

पटना स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में 29 अक्टूबर को आयोजित 'स्पेस एप्लीकेशन एडॉप्शन वर्कशॉप-2026' इसी सोच को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में सामने आई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से बिहार की परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समाधान विकसित करने तथा उन्हें धरातल पर लागू करने का आह्वान किया।

बाढ़ की चुनौती से निपटने में मिलेगी वैज्ञानिक मदद

बिहार में बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि खेती, आजीविका और जनजीवन को प्रभावित करने वाली बड़ी चुनौती है। उपग्रह आधारित निगरानी, वर्षा के आंकड़ों और नदियों के जलस्तर का वैज्ञानिक विश्लेषण बाढ़ की स्थिति को समझने तथा समय रहते तैयारी करने में उपयोगी हो सकता है। गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों के जल प्रवाह की बेहतर निगरानी से जल प्रबंधन और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने की संभावनाएँ भी खुलती हैं।

इसी दिशा में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (BIRSAC) और सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही 'टेककनेक्ट' पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है।

तकनीक का लाभ आम आदमी तक पहुँचे

इस पहल की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब वैज्ञानिक समाधानों का लाभ किसानों, आम नागरिकों और प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुँचे। कृषि नियोजन, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक का व्यावहारिक इस्तेमाल संसाधनों की बचत के साथ निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है।

बिहार की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक सोच से जोड़ने का संदेश भी इस कार्यशाला में उभरा। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की फीस व्यवस्था का उल्लेख करते हुए तकनीकी शिक्षा को युवाओं के लिए सुलभ बनाने की दिशा पर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

विकास की नई राह

अंतरिक्ष तकनीक, वैज्ञानिक आंकड़ों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय का इस्तेमाल यदि योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है, तो बिहार को बाढ़ प्रबंधन, कृषि और नियोजित शहरी विकास में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। अब असली कसौटी इन पहलों को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने और उनके परिणाम आम लोगों तक पहुँचाने की होगी। ■

Ideal atmosphere for multifacted growth



Come... experience it

Not just industry. Also commerce, institutions, living, education, sports, health, leisure, retail. Even the latest culturaland arts centres. In Greater Noida, it's all world class. And within reach, Enveloped in an atmosphere that's pollution free- amid growing greeners. Underlining holistic standards of living.

Facets of Greater Noida

Excellent Connectivity: • In proximity of two national and two state highways • Approachable from two 6-lane expressway • Intersection of Eastern and Western Freight Corridors • 20mins from proposed Jewar International Airport • Two metro lines will connect the city to Delhi and IGI Airport • 50 mins from Indira Gandhi International Airport

Meticulously planned with a host of international level facilities: • Weil-laid sewerage system • Drainage & rainwater harvesting • Water supply network • 24x7 uninterrupted power supply • Convergence network Plan Solid waste management plan

Equipped with robust and modern infrastructure for urban and social sector: • Ecologically Sensitive Areas • Spine of 130 mt. wide road • Ground Water Recharge Areas • Interlinked Greens • Energy efficient design & waste treatment • Solid Waste Management

Ease of doing business with transparency and efficiency: • Nivesh Mitra - A friendly single-window centralised portal & mobile application for investment: **www.niveshmitra.up.nic.in**

Greater Noida has become a showpiece of urban development with well-planned commercial, institutional, industrial residential and other areas of gainful living, employment and investment. Investors in any of a multitude of options have easy access to the Greater Noida Industrial Development Authority and will find that the terms of business are most attractive. Thus, this fast-developing city with a pollution-free environment has become a magnet for those seeking better living, working and investment opportunities.






Greater Noida Industrial Development Authority

Plot No. 01, Knowledge Park-04, Greater Noida 201308, Dist. Gautam Budh Nagar., U.P.
Helpline Center No.: 0120-2336046, 2336047, 2336048, 2336049
Ph.: 0120-2336030-33, E-mail: authority@gnida.in, Website: www.greaternoidaauthority.in

Follow us on

/OfficialGNIDA

JINDAL

PANTHER®

TMT REBARS & CEMENT

Desh ki Shaan,
Har Nirmaan ki Jaan



Anti-Corrosive | Tamper Proof Bag | High Compressive Strength | Eco-friendly and Sustainable

Toll free number: 1800 208 2008